

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 मार्च, 2005

(द्वितीय बैठक)

खण्ड-1 अंक-3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 22 मार्च, 2005

पृष्ठ संख्या

| | |
|---|-------|
| राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) | (3)1 |
| वर्ष 2004-05 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी कि त) प्रस्तुत करना। | (3)47 |
| प्राक्लन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। | (3)47 |

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 22 मार्च, 2005

(दूसरी बैठक)

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार एच0एस0 चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the discussion on Governor's Address will be resumed. Shri Naresh Malik was on his legs when the House adjourned at 1:30 P.M. today and he may continue his speech.

श्री नरे ा मलिक (हसनगढ़): स्पीकर सर, इस सरकार के गठित होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी भजन लाल जी ने एक बहुत बड़ा आ वासन दिया था कि पिछली सरकार ने जितने भी कर्मचारियों की छंटनी की है उन्हें सेवा में वापिस लिया जाएगा। कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष ने यह वायदा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी पुलिस कर्मचारी और जितने भी छंटनीग्रस्त/अधिकारी/कर्मचारी हैं सब को वापिस लिया जाएगा, इस आ वासन के बारे में सरकार विचार करे और सदन को अवगत करवाए। स्पीकर सर, आज सरकार बदल गई है लेकिन पूर्व व्यवस्था आज भी नहीं बदली है। आज ही कांग्रेस के मेरे एक

वरिष्ठ साथी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस, जिसका काम रोड ट्रैफिक को सुचारू करना है आज भी वह एक्साईज का काम कर रही है। ट्रकों को रोकना और उनसे धन उगाहना आज भी यही स्थिति है। ट्रैफिक पुलिस में आज भी इस तरह की बात चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ।

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को क्लैरिफिके इन देना चाहता हूँ तथा इनको बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के वक्त के जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्ज थे, जिनकी ये चर्चा कर रहे हैं, हमारी सरकार ने आते ही उन सब को पदमुक्त कर दिया है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अब वह सारा चार्ज एस0डी0ओ0 (सिविल) के पास है।

श्री नरे ा मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूँ कि मात्र एक हफता पहले मेरी फ़ैक्टरी के दो ट्रक सामान लेकर गए थे जिनके बिल और कागज बकायदा सब कुछ ठीक था उनसे फिर भी तीन हजार रुपए एंठे गए हैं। मेरे आदमियों ने गलती यह की कि उन्होंने पुलिस वालों के नम्बर नोट नहीं किए। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं यह जिक्र करना चाहूंगा तथा सरकार से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या सरकार नए और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यवाही करेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना

चाहूंगा कि जो पुराने उद्योग आज बन्द पड़े हुए हैं चाहे वे कर्ज के कारण पड़े हैं या किसी और कारण से बन्द पड़े हुए हैं क्या उन उद्योगों को फिर से चलाने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है या सरकार इस बारे में कुछ विचार कर रही है। जो उद्योग बन्द पड़े हैं क्या सरकार कोई सहायता देकर या कुछ देकर उन उद्योगों को चालू करवाने की कोई कोशिश करेगी। स्पीकर सर, शिक्षा के बारे में पिछली सरकार ने जो नीतियां अपनाई थीं वह ठीक नहीं थी, चाहे मिडल स्कूलज थे या प्राइवेट हाई स्कूलज थे और जितने भी अन्य स्कूलज थे उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी और उनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही थीं। वे लोग माननीय एजुकेशन मिनिस्टर जी से मिले भी हैं। पिछली सरकार के गलत रवैये ने उन्हें परेशान किया है। स्कूलों की हालत ठीक करने के बारे में सरकार विचार करे। आज हम कहते हैं कि सदन में विपक्ष नहीं है।...

Mr. Speaker : No. No. This is not the way. This is not to be recorded Mr. Malik, your time is over. Please take your seat. (Interruptions) Please conclude your speech in one minute.

श्री नरेण्डर मलिक : अध्यक्ष महोदय, इस समय माननीय फाईनैस मिनिस्टर जी हाउस में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं साम्पला में दीनबन्धु सर छोटू राम अकादमी के बारे में अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि जिस समय मैंने पहले इसका जिक्र किया था उस समय माननीय वित्त मन्त्री जी हाउस में नहीं थे।

पिछली सरकार ने साम्पला में एक स्कीम लागू की थी कि पूरे साम्पला गांव और गढ़ी गांव को एक आदर्श गांव बनाया जाएगा। पिछली सरकार ने इसके बारे में घोशणा की थी और अब भी उसका कार्य चल रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी दीन बन्धु सर छोटूराम जी के नाते से भी हैं, मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे इस योजना को भीघ्न पूरा करवाएं। स्पीकर सर, पिछले कल सदन में यह बात चली थी कि गोवा में हाउस कैपचर हो गया और झारखण्ड में कैपचर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा में इनकी इतनी मैजोरिटी है कि वहां पर हाउस कैपचर नहीं होगा। स्पीकर सर, इन्हीं भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी सीट पर बैठता हूं।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल (अम्बाला कैट) : स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसके बाद मैं राज्यपाल महोदय का और पार्लियामैंट्री मिनिस्टर का तथा दूसरे साथियों का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें हरियाणा में होने वाले कामों के बारे में अवगत करवाया। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूं कि 6 महीने पहले अम्बाला छावनी में फ्लड आया था और वहां पर सैकड़ों-करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। उस फ्लड के दौरान अम्बाला छावनी में रिहायशी इलाकों की कोई गली और इन्डस्ट्रीज ऐसी नहीं थी जहां पर पानी नहीं आया था, उस समय पानी की वजह से वहां पर काफी नुकसान हुआ था।

पिछली सरकार ने अम्बाला छावनी को बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित नहीं किया था जिसकी वजह से वहां पर चाहे निम्न स्तर के लोग थे, मिडिल स्तर के लोग थे या उच्च वर्ग के लोग थे या अन्य लोगों का जो भी नुकसान हुआ था उसका उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाया था जबकि वे मुआवजेके हकदार थे। मेरा सरकार से निवेदन है कि अम्बाला छावनी को बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित करके उसका दोबारा सर्वे करवाकर सभी वर्गों के लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान किया जाए। स्पीकर सर, इसके साथ मैं सदन में यह भी बताना चाहूंगा कि पहले अम्बाला छावनी में संसार में सार्इटिफिक इन्स्ट्रूमैंट्स का एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब पिछले 10 सालों से अम्बाला छावनी में सार्इटिफिक इन्स्ट्रूमैंट्स इन्डस्ट्री का नामोनिशान नहीं है। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि अम्बाला छावनी में इन्डस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिक पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि सरकार कुछ ऐसे स्टैप्स उठाए जिससे अम्बाला छावनी की इन्डस्ट्री अपलिफट हो और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके तथा अम्बाला छावनी में इम्प्लायमेंट बढ़ सके। स्पीकर सर, हरियाणा में प्रोपर्टी बेचने के लिए कहीं पर भी नो-आब्जैक्शन सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन पिछली सरकार ने इसको अम्बाला छावनी में ही इम्प्लीमेंट कर दिया था। नो-आब्जैक्शन सर्टिफिकेट लेने के नाम पर पिछली सरकार लोगों से हजारों रुपए लेती रही है। प्रोपर्टी को बेचने के लिए नो-आब्जैक्शन सर्टिफिकेट लेना पूरे हरियाणा में सिर्फ अम्बाला छावनी में ही है। यह नीति पिछली सरकार ने जनता को

परेशान करने के लिए बनाई थी। मेरा सरकार से निवेदन है कि नो-आब्जैक्शन सर्टिफिकेट लेने की नीति को खत्म किया जाए। स्पीकर सर, जिस आदमी के घर में बेटी की शादी हो और उसको उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है अगर उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है तो उससे भी 15-15 हजार रुपए नो-आब्जैक्शन सर्टिफिकेट देने के नाम पर दिए जाते रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस नीति को जो पिछली सरकार ने शुरू की थी इसको बंद किया जाए। जो कंडीशन पिछली सरकार ने लगाई थी वह गैर कानूनी है। किसी भी म्यूनिसिपल एक्ट के किसी भी सैक्शन में और किसी भी क्लॉज में ऐसा कहीं पर भी मेशन नहीं है एन0ओ0सी0 लेने की कोई आवश्यकता है। इसके अलावा अम्बाला छावनी के अन्दर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे पहले कांग्रेस सरकार के वक्त में 700 रुपए सालाना लीज के रूप में लिए जाते थे। पिछली सरकार के वक्त में उन स्कूलों पर लीज की रकम 25-25 और 30-30 लाख रुपए सालाना कर दी गई है। यानि कि चार-चार हजार गुणा लीज बढ़ा दी गई थी। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो प्राइवेट स्कूल हजारों बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं उनको राहत देने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं। पिछली सरकार ने एक ऐसी घोषणा की थी कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसा न किया जाए क्योंकि प्राइवेट स्कूल ही हरियाणा में जनता को प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं। हरियाणा में 30 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों से एजुकेशन ले रहे हैं।

स्पीकर सर, पूर्व सरकार ने अपने मोटिव के लिए और अपने परप्पज को हल करने के लिए ऐसे स्टैप उठाए ताकि वे अपनी मन्थली इन्कम का सोर्स बन सकें। अब नया सैशन शुरू हो गया है और एडमिशन शुरू हो गई हैं लेकिन बच्चों के सामने और टीचर्स के सामने समस्या आ रही है कि कहीं ये स्कूल बंद तो नहीं हो जाएंगे। इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर प्रार्थना है कि स्कूलों की और बच्चों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार तुरन्त उचित कदम उठाये ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बात अपने हलके की सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे हलके में सबसे बड़ी प्राब्लम सड़कों की है। पिछले दस सालों में वहां की सड़कें खत्म हो चुकी हैं। उनमें इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि अगर कोई स्कूटर ड्राइवर वहां पर गिर जाता है तो या तो ड्राइवर को निकालना पड़ेगा या फिर स्कूटर को निकालना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सड़कों को बनाने के लिए जो बजट दिया गया था वह कहाँ गया। मेरा निवेदन है कि मेरे हलके की सड़कों को तुरन्त ठीक कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला छावनी के अन्दर गंदगी इतनी ज्यादा फैल गयी है कि अगर उसको फैलने से रोका नहीं गया तो अम्बाला छावनी के साथ-साथ आसपास के दूसरे एरियाज में भी पीलिया फैल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल

महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

Shri S.S. Surjewala : Sir, I want to speak on a point of order. Please educate the new members because they are not speaking relevant. It seems that they are not speaking on the Budget. They should speak on the policy and on the Governor's Address. I do not want to interrupt. I want to say that they may please be educated. Policy matters should be discussed. The individual questions regarding constituency can be discussed at other time.

डा० सीताराम (एस०सी०, डबवाली) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय दिया उसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। राज्यपाल के अभिभाषण में आने वाले समय के लिए सरकार की नीतियों के बारे में एवं सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा किस प्रकार करेगी, किस प्रकार से विकास के कामों को अंजाम देगी, को दर्शाया गया है। इसके अंदर कृषि क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की गयी है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की जो 70 प्रतिशत जनता है वह कृषि के ऊपर ही आधारित है और अपना रोजगार वह कृषि ही से चलाती है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक और बात पर जोर दिया गया है और वह बात है कि कृषि का विविधीकरण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि कृषि का विविधीकरण किया जाना चाहिए लेकिन इसके लिए

सरकार किसानों को क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाएगी, किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम लाभकारी मूल्य किस प्रकार दिया जाएगा एवं फसलों की खरीद उचित समय पर हो सके क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी ताकि जो किसान अपनी फसल चक्र को बदलने का प्रयास करेंगे उनको किसी भी प्रकार का घाटा न उठाना पड़े। कोई ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए जिससे किसान परेशान न हों लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर ऐसा कोई ठोस उपाय इस बारे में नहीं दर्शाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो इलाका है वह कॉटन बेल्ट का इलाका है। वहां पर इस बार कॉटन की बम्पर क्राप हुई है लेकिन जो केन्द्र सरकार की सी0सी0आई0 नाम की एजेंसी है उसने कॉटन का जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया वह बहुत कम किया है। अध्यक्ष महोदय, कॉटन की फसल की कृषि करने के लिए काफी खर्चा आता है लेकिन न्यूनतम मूल्य पर भी किसानों की इस फसल को वहां पर नहीं खरीदा गया। किसान मंडी के अंदर 15-15, 20-20 दिन अपनी फसल को बेचने के लिए बैठे रहते थे। (विधन) ठीक है, सरकार जरूर हमारी थी लेकिन वह एजेंसी तो केन्द्र सरकार की है और वही इस फसल की खरीद करती है। केन्द्र में तो आपकी सरकार थी अगर आप चाहते तो उन किसानों को न्यूनतम मूल्य से ज्यादा दाम दिलवा सकते थे और समय पर उसकी खरीद करवा सकते थे लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने वायदे तो किए लेकिन उन बातों को अंजाम देने में आप नाकाम रहे। अध्यक्ष महोदय, फसलों के विविधीकरण

की जो बात कही गई है उस बारे में मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ठोस कार्य और उपाय किए जाएं ताकि किसान फसलों के विविधीकरण की ओर आकर्षित हो सकें और उसे घाटा न उठाना पड़े। आज के जमाने में खेती कोई लाभकारी व्यवसाय नहीं रह गया है। आज किसान की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए इस सरकार को और अच्छे कदम उठाने चाहिए। किसान पर ओलावृष्टि की प्राकृतिक मार भी पड़ी है जिसके अंदर फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा है कि ओलावृष्टि के लिए सरकार ने मुआवजा राशि देने की घोषणा की है और स्पेशल गिरदावरी की घोषणा की है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी जब विपक्ष में थे तब उन्होंने ओलावृष्टि के लिए प्रति एकड़ दस हजार रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की थी। आज उनकी सरकार है मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि अब वे अपनी बात को लागू करवाने का प्रयास करेंगे। (विध्न) मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो कि उन्होंने कही थी। नहरी पानी के समान वितरण के लिए भी आदरणीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर जिक्र किया गया है। जब हरियाणा प्रदेश बना उस समय भी कांग्रेस का शासनकाल थी। उस समय से पानी वितरण की प्रणाली चली आ रही है। बीच में थोड़े समय के लिए हमारा शासन आया। इस दौरान हमने उस वितरण प्रणाली के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। अब नहरी पानी का वितरण सरकार किस तरीके से करेगी? क्या उत्तरी हरियाणा के पानी का हिस्सा काटकर किसी और दूसरे

हिस्से को दिया जाएगा? इसके बारे में सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए।

श्री एस0एस0 सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, 100-100 डायरैक्ट मोगे नहरों में लगा रखे हैं जो कि लगा नहीं सकते हैं और इनके यहां एक-एक फार्म पर पूरा पूरा रजवाहा चल रहा है।
(विघ्न)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सिंचाई के लिए दादूपुर नलवी नहर का भी जिक्र किया गया है। यह कार्य भी हमारी सरकार के समय में मंजूर किया गया था। इसमें ऐसा नया कुछ भी नहीं। दूसरे इस अभिभाषण में एस0वाई0एल0 नहर का जिक्र किया गया। इसके बारे में आदरणीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर स्पष्ट नहीं बताया गया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कब तक लागू करवाएगी क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब भी कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र में भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से यह कार्य अब रुके इसलिए एस0वाई0एल0 नहर का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाना चाहिए। अभिभाषण में यह भी नहीं बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इस नहर को बनवाएंगे या बातचीत के माध्यम से इसको बनवाने का काम करेंगे। अभिभाषण में कहीं भी नहीं दर्शाया गया कि नहर के काम को पूरा करने के लिए पैसे का

प्रबन्ध कैसे किया जाएगा। इसके अलावा इस अभिभाषण के अन्दर यह जिक्र किया गया है कि नई औद्योगिक पोलिसी बनाई जाएगी परन्तु यह जिक्र नहीं किया गया कि पिछली सरकार की जो औद्योगिक पोलिसी थी उसमें क्या कमियां थीं। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस तरह से उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अभिभाषण में कहीं भी यह स्पष्ट नजर नहीं आता जिससे हमें यह विश्वास हो जाए कि हरियाणा में और ज्यादा उद्योग लगा सकते हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के व्यापारिक वर्ग से यह वायदा किया था कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर कांग्रेस की सरकार आयेगी तो वैट प्रणाली को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक सारे भारतवर्ष में यह प्रणाली लागू नहीं हो जाती। इसके बारे में भी अभिभाषण में कोई स्पष्ट बात नहीं की गई कि यह सरकार उस वायदे को पूरा करेगी या नहीं।

Mr. Speaker : Please wind up, Dr. Sahib.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव के समय यह वायदा किया गया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार आयेगी तो बेरोजगारी की समस्या को हल कर देंगे। मुझे लगता नहीं कि इस सरकार के पास कोई जादुई छड़ी होगी जिससे इस समस्या का समाधान कर देंगे। सरकार इस समस्या को हटाने का काम करेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ हरियाणा प्रदेश के अन्दर नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष में है। इसको दूर करने के लिए

राज्यपाल के अभिभाषण में कोई विशेष रूप से जिक्र नहीं किया गया है।

Mr. Speaker : Please wind up.

डॉ० सीता राम : बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो पूरे भारतवर्ष के अन्दर है। आज जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कोई नीति बनाएगी या जनसंख्या वृद्धि को कम करने का कोई काम करेगी? इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं उसके बारे में क्या सरकार कोई ऐसे कदम उठाएगी कि गांवों के लोगों को गांव के अन्दर ही वे सब सुख सुविधाएं दी जा सकें जो शहर के लोगों को मिलती हैं ताकि वे शहरों की ओर पलायन करना बन्द कर दें।

Mr. Speaker : Thank you very much Dr. Sahib. Please take your seat.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Speaker Sir, as Shri Shamsheer Singh Surjewala Ji, Senior member of the House has also pointed out that if you want a tone to be set for the newly elected members, you must give some time to senior member after two members because they are to draw inspirations from senior members.

Mr. Speaker : Yes, Mr. Birender Singh Ji, I am doing that.

Sardar Paramvir Singh (Tohana) : Sir, I want to thank his excellency the Governor of the Haryana for his address to this House citing priorities of the Congress Government. I also want to congratulate the Congress Government of Haryana for having visionary approach and touching problems of all sections of the society with deep understanding and having a commitment of all around development of this State. The development should not be in one particular area like we saw earlier. I mean lop sided approach, what we saw earlier and we have been absolutely myopia vision of the previous Government with regard to development. The previous Government made the enormous wastage of Public funds. I will say, not even 30% of the grants on the ground level were utilized. Rest of the grants were misappropriated and it should be enquired into. I want to draw the attention of the Government for the loss suffered by the farmers due to hailstorm and the compensation was disbursed just one day before the counting of votes on 26th February, 2005. Many genuine people were left out from the compensation. If genuine people left out, it should be checked again. Recently the loss has been incurred by the seasonal rain and high velocity wind, which has caused loss to the standing wheat crop. The loss should be assessed and the farmers should be given relief. Thank you.

श्री दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे गरिमापूर्ण सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय दिया और साथ ही सभी नव निर्वाचित विधायकों को

बधाई देता हूं और मैं प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार और भय और आतंक के माहौल से मुक्ति दिलाई। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के अन्दर सरकार की मंशा के बारे में राज्यपाल महोदय ने बहुत कम बताया है। पिछले पांच-साढ़े पांच वर्ष के अन्दर इस प्रदेश की व्यवस्थाएं चरमरा गई थीं व आम आदमी का प्रजातन्त्र से विश्वास उठा चुका था। मैं इस प्रदेश की जनता को विशेष तौर पर बधाई देता हूं जिन्होंने इस बात का अहसास किया और प्रजातांत्रिक तरीके से सारे माहौल को एक क्षण में पलट कर के रख दिया। आज प्रदेश के लोगों की आशाएं थी, आकांक्षाएं थी कि नई सरकार आएगी और नई नीतियां लेकर आएगी और उन्हीं नीतियों का उल्लेख राज्यपाल महोदय जी ने अपने अभिभाषण में किया है। बहुत सी चीजों के बारे में इस अभिभाषण के अन्दर बताया गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज नई सरकार ने की है, जिन के बारे में मैं सरकार को और विशेषकर मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। हमारा यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां के लोगों की मुख्य आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। मैं समझता हूं कि राज्य की अर्थ व्यवस्था का मूल आधार भी कृषि है, इस कृषि के क्षेत्र के अन्दर जो सरकार ने नीति अपनाई है वह काबिले तारीफ है इस बात की ही दक्षिणी हरियाणा के लोग सालों से अपेक्षा करते थे हरियाणा प्रदेश बनने के बाद एक तरफ तो कुछ क्षेत्रों ने सूखे की मार झेली है और दूसरी तरफ इसी प्रदेश का क्षेत्र ज्यादा पानी आ जाने से सेम की मार झेल रहा था। एक तरफ तो सेम की समस्या

से निपटने के लिए पैसे का प्रावधान करना पड़ता था और दूसरी तरफ हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ा था, हमारे क्षेत्र में लोगों ने पानी के लिए 1400 फुट गहराई तक खुदाई की। इतनी गहरी खुदाई के बाद वहां पानी मिला भी तो वह भी खारा पानी और बहुत कम मात्रा में। आज मुख्यमंत्री महोदय और सरकार ने एक ऐसी आशा की किरण हममें जगाई है कि जो पानी आज हरियाणा में मौजूद है उसका समान और न्यायोचित बंटवारा किया जाएगा। इसके लिए मैं सरकार और विशेषतौर पर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने आते ही हमारी उस समस्या की तरफ ध्यान दिया। साथ ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हम भी उस क्षेत्र के वासी हैं जहां पानी बहुत कम है उसके रिचार्ज की तरफ भी ध्यान देकर मौजूदा सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जहां तक एस0वाई0एल0 की बात है, एस0वाई0एल0 को जीवन रेखा तो सभी कहते रहे हैं लेकिन उसका पानी हमें किस तरह मिले इस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया और न ही पानी लाने के लिए ठोस प्रयास किए गए। हमारी मौजूदा सरकार ने आते ही उसको प्राथमिकता दी है। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि से जुड़ी हुई है और हमारा पुरजोर प्रयास रहेगा कि हम केन्द्र के नेताओं से मिलकर, अपने बड़े भाई पंजाब के नेताओं से मिलकर एस0वाई0एल0 का पानी इस पंचवर्षीय योजना में हरियाणा प्रदेश में लेकर आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, कृषि बिजली पर निर्भर करती है और दक्षिणी हरियाणा के किसान तो पूरी तरह से बिजली पर ही निर्भर रहते हैं। सरकार ने आते ही बिजली की कीमतों को

सुधारने के लिए जो प्रयास किए हैं उसको देखते हुए जो सालों साल से बिलों की रिकवरी पैडिंग पड़ी थी उसके ऊपर भी सरकार ने चेतना और चिंता जताई है। हमें आशा है कि बिजली के जो बिल किसानों के बकाया पड़े हैं उनका हल निकालने के लिए न्यायोचित, वायवल सोर्सिज ढूंढने पर सरकार विचार करेगी जो कि बहुत अच्छी शुरुआत होगी। अध्यक्ष महोदय, किसानों के ऊपर लाखों रुपए के बिजली के बिल बकाया हैं। कृषि की कमाई से किसान वे बिल पे नहीं कर सकते। पहले वाली सरकार के समय में जब कोई ट्रांसफार्मर जल जाता था तो किसान को कहा जाता था कि पहले पैडिंग बिल जमा करवाओ उसके बाद ट्रांसफार्मर बदला जाएगा जिस कारण किसान की खड़ी फसल पानी के अभाव में नष्ट हो जाती थी। इस तरह से जुल्म पिछली सरकार के समय से किसानों पर होते थे। हम अपनी सरकार से आशा करते हैं कि इसका भी न्यायोचित हल बहुत जल्दी सरकार निकालेगी ताकि किसान आने वाली समय में बकाया बिलों का भुगतान करके नए बिलों को समय पर जमा करवा सके। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है। यह बात ठीक है कि हरियाणा के लिए कहा जाता है कि *there is no agriculture except culture*. हम कृषि पर निर्भर करते हैं लेकिन किसी भी प्रदेश का चहुंमुखी विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें उद्योगों को साथ लेकर नहीं चला जाएगा। हरियाणा के अंदर पिछले पांच सालों के अंदर जिस तरह का माहौल था उससे सभी उद्योगपति इतना घबराये हुए थे कि वे अपने-अपने उद्योगों की न

केवल यहां से पलायन की बातें करते थे बल्कि आने वाले उद्योगपतियों को भी कहते थे कि वे तो यहां फंस चुके हैं तुम यहां आकर गलती मत करना। सरकार की गलत नीति की वजह से हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। हमारा प्रदेश तीन तरफ से दिल्ली से लगता है। इस प्रदेश की भौगोलिक और औद्योगिक स्थिति इस तरह की बन सकती थी कि दुनिया में हम एक नम्बर पर हो सकते थे। अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव जैसी नगरी जहां पर सर्वप्रथम मारूति उद्योग आया था आज उसकी वजह से हम अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर चले गए हैं। इसी तरह से और भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस प्रदेश के अंदर आएंगे तो इस प्रदेश के चहुंमुखी विकास में और अर्थव्यवस्था में दिन रात का फर्क पड़ सकता है। मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहां उद्योग लगाने के लिए सुविधाएं दे। गुड़गांव की तरह ही हमारे महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जैसे पिछड़े इलाकों में भी उद्योग लगाए जाएं। उद्योग लगने से जहां प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब तक प्रदेश का हर नागरिक शिक्षित नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेता है। आज शिक्षा को कमर्शियल ओरियंटिड करके रख दिया है। अभी किसी साथी ने प्राइवेट स्कूलों का जिक्र

किया। मैं मानता हूँ कि सरकारी शिक्षा संस्थानों के अंदर उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करवाई जाती जितनी प्राइवेट स्कूलों में करवाई जाती है। लेकिन हर व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता और न ही वह उनकी फीस वहन कर सकता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ से अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थानों का प्रावधान किया जाए जिनमें अच्छी पढ़ाई हो और गरीब बच्चे उनमें अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में समानता के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। दक्षिणी हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में आज तक उपेक्षित रहा है। वहां पर न तो मैडिकल कालेज है, न इंजीनियरिंग कालेज है, न कोई विश्वविद्यालय है और न ही किसी विश्वविद्यालय की वहां ब्रांच है। अगर मुख्यमंत्री जी और सरकार चाहे तो प्रदेश की समानता को देखते हुए दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक विश्वविद्यालय अवश्य दे ताकि यहां के लोग शिक्षा से वंचित न रहें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूंगा। किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी धरोहर उस प्रदेश के स्वस्थ नागरिक होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर किसी प्रदेश के नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो वह प्रदेश आगे नहीं जा सकता। पिछले पांच सालों में प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। सरकारी अस्पताल में अगर जाते थे तो वहां पर या तो डाक्टर नहीं मिलते थे या फिर दवाई नहीं मिलती थी। दवा मिलती थी तो बड़े भारी पैसे वाली ऐसी दवाई लिख दी जाती थी जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। जिन कम्पनियों की

दवाइयों पर डाक्टरों को कमीशन अधिक मिलता था उन कम्पनियों की बनी दवाई लिख दी जाती थी। अस्पताल में बीमारियों के टैस्टों का भी कोई इन्तजाम नहीं है। बीमारियों के सारे टैस्ट सरकारी अस्पताल में न होकर प्राइवेट लैबज में होते थे। मौजूदा सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य की तरफ चिन्ता जताते हुए प्रदेश के हर नागरिक को अच्छी चिकित्सा सुविधा देने की बात कही है ताकि आगे आने वाले समय के अन्दर न केवल हमारे नागरिक स्वस्थ हों बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी हमारे प्रदेश के बारे में पूरे देश के अन्दर चर्चा की जा सके। अध्यक्ष महोदय, जो स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हैं मैं समझता हूँ कि उनमें एम0एल0आर0 काटने के अलावा कुछ नहीं किया जाता। चाहे 325 का केस है या 326 का केस है, इस तरह के केसिज वहाँ पर दर्ज होते रहे हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों की इस प्रकार की मानसिकता से लोग ग्रस्त रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिन कमियों का सरकार अहसास कर रही है निश्चित तौर पर उन कमियों को दूर करने पर सरकार ध्यान देगी। अब भविष्य में अस्पतालों के अन्दर एम0एल0आर0 काटने के बजाय लोगों का उपचार होगा। लोगों का उपचार होगा तो तभी हम लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इन बातों की तरफ ध्यान देगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं जनस्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूंगा। जनस्वास्थ्य के प्रति भी प्रदेश के कई हिस्से पिछली सरकार में उपेक्षित रहे हैं जहाँ पर आज तक मिनिमम

हाईजेनिक कंडीशन भी पूरी नहीं की गई। इस बारे में मेरा कहना है कि मेरा क्षेत्र विशेष तौर पर ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें जन स्वास्थ्य सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। जब सरकार सारे प्रदेश के लोगों की सुख सुविधा के बारे में सोचती है तो सरकार को उन क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए जिन क्षेत्रों की तरफ पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। डाक्टर साहब अभी बोलते हुए कह रहे थे कि लोगों का पलायन गांवों से शहरों की तरफ और कस्बों की तरफ हो रहा है। यदि शहरों वाली सुविधा गांवों के स्तर पर या कस्बों के स्तर पर मिलेगी तो यह पलायन की प्रवृत्ति स्वतः रुक जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को पुनः बधाई देता हूँ और यह आशा और अपेक्षा रखते हुए कि जो बातें अभिभाषण के माध्यम से लोगों के सामने रखी हैं उनको सरकार पूरा करेगी ताकि जिस भावना से लोगों ने हमें जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा है उनकी वह भावना पूरी हो सके, धन्यवाद।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो समाज है यह पुरुष प्रधान समाज है। हरियाणा में खासतौर पर महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। डावरी और डोमेस्टिक वायलेंस के केस हम रोजाना देखते और सुनते हैं। हम यहां पर एक तरफ महिला सशस्त्रीकरण यानि वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे हरियाणा में

लड़कियों की संख्या लड़कों के अनुपात में कम होती जा रही हैं। इसके लिए हमारे कई लाज बन चुके हैं किन्तु इनको किसी ने स्ट्रिकटली फालों नहीं किया। स्पीकर साहब, हमें इस दिशा में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यह सोचकर रोंगटे खड़े होते हैं कि अगर इसी प्रकार से लड़कियों की संख्या कम होती गई तो कल को हमारी बहू-बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे इतने भाइयों ने अपनी अपनी बात कही लेकिन एक दो को छोड़कर किसी ने भी महिलाओं की बात नहीं उठाई। महिलाओं की कुछ ऐसी बेसिक नैसेस्टिज हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है। जैसे कि शौचालय है, आप किसी गांव में चले जाएं तो वहां पर 70 परसेंट महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। शौचालय न होने के कारण उनको बहुत मुश्किल होती है। वे शौच के लिए या तो सुबह 4.00 बजे उठकर जाती हैं या रात के अन्धेरे में जाती हैं। आपने भी देखा होगा कि रात के समय लड़कियां जब शौचालय के लिए घर से निकलती हैं तो बहुत सी लड़कियों के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं और वित्त मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं। मैं इस बारे में इनसे निवेदन करूंगी कि जब हमारा अगला बजट आए तो उसमें महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनके लिए खास प्रावधान रखा जाए। महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सी स्कीम्ज हैं जो महिलाओं के लिए आती हैं। वे स्कीम्ज उन महिलाओं के लिए होती हैं जो शिक्षित नहीं हैं या जो पावर्टी

लाइन के नीचे रहती हैं। वे इन स्कीम्ज का फायदा नहीं उठा सकती क्योंकि इन स्कीमों के बारे में न तो उनको कोई ठीक तरह से बताता है और न ही कोई समझाता है। इसके लिए अगर हो सके तो हमें सिंगल विंडो सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कुछ एन0जी0ओज0 भी हों और कुछ एम्पलाइज भी हों जो वहां पर उसी स्थान पर महिलाओं से संबंधित जितनी भी स्कीम्ज हैं उनकी जानकारी दे सकें। ओल्ड ऐज पेंशन की स्कीम है या कुछ ऐसी स्कीम्ज हैं जहां पर महिलाओं को लोन्ज दिया जाता है या रोजगार देने के लिए अथवा अपना छोटा मोटा काम करने के लिए जानकारी दी जाती है। इन सबकी जानकारी देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होना अनिवार्य है। जिससे महिलाएं उन स्कीमों का फायदा उठा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि हमारे बहुत से भाई-बहन बोलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि लड़कियों की शिक्षा फ्री है लेकिन इसमें भी बहुत सी कमियां हैं। हम लोग जब गांवों में जाते हैं तो लड़कियां और उनके मां-बाप यह कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए कहने को तो शिक्षा फ्री है लेकिन इसमें कई ऐसी चीजें लगा दी जाती हैं कि वे लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं जैसे बिल्डिंग एलौटमेंट के लिए कुछ पैसा लेते हैं या कुछ और दूसरी चीजों के लिए पैसा लेते हैं जिससे शिक्षा फ्री नहीं रहती है। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसमें लड़कियों को दी जाने वाली शिक्षा पर उनको खर्च न करना पड़े बिल्कुल फ्री एजुकेशन हो और उनको किताबें व दूसरा सामान फ्री मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय,

मैं इतना ही कह कर आपका धन्यवाद करती हूँ और अपना स्थान ग्रहण करती हूँ।

श्री नरेश यादव (अटेली) : आदरणीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नई सरकार को मैं बधाई देता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार पहले भी रही है लेकिन पहली बार इस सरकार ने यह माना है कि पानी के मामले में दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है। केवल पानी के मामले में सरकार ने स्वीकार किया है कि दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि केवल पानी की ही बात नहीं है, दक्षिणी हरियाणा के साथ हर क्षेत्र में भेदभाव हुआ है। जो भी मुख्यमंत्री बने वे सभी चीजें अपने क्षेत्रों में ले गए। सबसे पहले तो हमारे हिस्से का पानी हमें अभी तक नहीं मिला। ये लोग भी अभी बोल रहे थे और कांग्रेस पार्टी के लोग भी बोल रहे थे लेकिन किसी ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि दक्षिणी हरियाणा का कितना पानी दूसरे क्षेत्रों में है। स्पष्ट रूप में दक्षिणी हरियाणा का महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, गुड़गांव, अहीरवाल बैल्ट का कितना पानी दूसरे क्षेत्रों में है और कितने साल से है इस तरफ किसी ने सदन का ध्यान आकृष्ट नहीं किया। जो भी मुख्यमंत्री बना किसी भी चीफ मिनिस्टर से इस बारे में कुछ काम नहीं किया। हमारे इलाके में 1400 फीट पानी नीचे चला गया है और 150 गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। आज भी हमारे पास

पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि नई सरकार बनी है वह पानी देगी एस0वाई0एल0 बनेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ और पिछले 10 सालों से हम लोग सड़कों पर लाठी भी खा रहे हैं और जेल में भी जा रहे हैं। सभी सरकारों में हमने जेल काटी है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय हालत यह है कि हमारे दक्षिणी हरियाणा में पीने का पानी नहीं है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे और एस0वाई0एल0 के ऊपर कहा गया है कि कुछ किया जाएगा। एस0वाई0एल-एस0वाई0एल0 सुनते हुए बहुत साल हो गए और इस पर बहुत राजनीति भी हो गई। पंजाब के लोग भी एस0वाई0एल0 पर राजनीति कर रहे हैं और हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां भी एस0वाई0एल0 पर राजनीति कर रही है। आज एक डैड लाइन खींच देनी चाहिए कि एस0वाई0एल0 कब बनेगी, किस दिन बनेगी? अगर नहीं बनेगी तो सदन में जितने भी मैम्बर्ज हैं क्या सभी लोग एस0वाई0एल0 के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? जैसे पंजाब के लोगों ने फैसला कर दिया और पंजाब की सरकार ने पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया और यह कह दिया कि हम हरियाणा को एक बून्द पानी की नहीं देंगे और ना किसी समझौते को मानेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि सदन में जो पहले सदस्य थे उन्होंने इस बात के लिए क्या कोई कार्यवाही की है? हम तो नये सदस्य चुन कर आये हैं। प्यासे तो हम मर रहे हैं और इलाका भी हमारा बर्बाद हो रहा है जबकि पानी के ऊपर सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि दक्षिणी हरियाणा में पानी तो है नहीं। भगवान ने कुछ पहाड़ दिये थे कुछ नदियां दी थीं जो कि सूख गई, उन पर भी पिछली सरकार की ऐसी नजर पड़ी कि पहाड़ों की भी लीज उठा दी। वहां पर इनका एक ही मालिक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की सारी लीज, सारे पहाड़ और क्रैशर रोड़ी की ब्लैक मार्कीटिंग हो रही है। इन चीजों पर कई तरह के टैक्स नाजायज लगे हुए हैं। अभी भी कुछ लोग वहां पर इल्लीगल बैठे हुए हैं। आपकी सरकार तो बन गई है। आप लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई है इस बारे में काफी लोगों ने भाषण दिये और कहा कि पिछली सरकार ने लोगों को तंग किया। अध्यक्ष महोदय, वहां पर अभी भी वही लोग कमा रहे हैं और वही लोग फायदा उठा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त प्रभाव से इन लीजों को कैंसिल किया जाए और नये लोगों को इसका फायदा उठाने दिया जाए। साथ ही सरकार से निवेदन है कि उन लोगों पर अंकुश लगाया जाए। इसके अलावा स्पीकर सर, अस्पतालों में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अटेली मण्डी में एक सिविल अस्पताल है और हरियाणा में 10 वर्षों से कांग्रेस, इन्डो और एच0वी0पी0 की सरकारों ने राज किया है लेकिन उस अस्पताल में एक्स-रे मशीन नहीं है। वहां एक एक्स-रे मशीन आई थी लेकिन आज तक उस बारे में कुछ नहीं पता है कि वह कहां पर है। मैं पिछली सरकार के वक्त में उस अस्पताल में गया था और वहां स्टाफ से पूछा था

कि हमारे अस्पताल की एक्स-रे मशीन कहां पर है तो मुझे जवाब दिया गया कि वह खराब हो गई है रिपेयर के लिए गई हुई है। उसके बाद मैं दोबारा अस्पताल के सी०एम०ओ० के पास गया और उनसे भी पूछा कि हमारे अस्पताल की एक्स-रे मशीन कहां पर है तो मुझे जवाब दिया गया कि वह खराब हो गई है और रिपेयर के लिए गई हुई है। उस वक्त मैं एम०एल०ए० नहीं था लेकिन स्पीकर सर, उस एक्स-रे मशीन का आज तक पता ही नहीं है कि वह कहां पर है।

Mr. Speaker : Please wind up. (Interruptions)
Please have patience.

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, इसके बाद मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा कि हरियाणा में हमारे महेन्द्रगढ़ जिले के सबसे ज्यादा लोग समय पर बिजली का बिल देते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो अपने यहां पर उपस्थित अधिकारियों से जानकारी ले सकते हैं। इस सबके बावजूद हमारे महेन्द्रगढ़ जिले में सारे हरियाणा से सबसे कम बिजली दी जाती है और सबसे ज्यादा जले हुए ट्रांसफार्मर्ज भी आपको हमारे महेन्द्रगढ़ जिले में ही मिलेंगे। वहां पर न बिजली है, न सही ट्रांसफार्मर्ज है और न ही नहरी पानी है। स्पीकर सर, जब वहां पर नहरी पानी नहीं है तो सरकार को चाहिए कि वहां पर बिजली को सब्सीडाईज्ड दामों पर दिया जाना चाहिए।

Mr. Speaker : Thank you, Please wind up. Mr. Yadav.

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, मैं कुछ मामलों के बारे में और कहना चाहता हूँ। स्पीकर सर, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे इलाके के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। जहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं वहीं पर यूनिवर्सिटी खोल दी जाती है। अभी पिछली सरकार के वक्त में ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौधरी देवी लाल जी के नाम से यूनिवर्सिटी अपने एरिया सिरसा में खोल दी। हम तो यह कहते हैं कि हमें नाम से कोई प्रोब्लम नहीं है आप उस यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी देवीलाल ही रख लेते लेकिन उसको हमारे इलाके में खोल देते ताकि वहाँ की जनता का भी भला हो जाता। स्पीकर सर, हमारा इलाका सैनिकों का इलाका है और कारगिल युद्ध में हमारे इलाके से 133 फौजी शहीद हुए थे लेकिन वहाँ पर फौजियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है न ही वहाँ पर कोई सैनिक स्कूल है, न कोई सैनिक अस्पताल है और न ही दूसरी कोई सुविधाएं हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह सरकार दक्षिणी हरियाणा की तरफ भी गौर करे। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Now, Sh. Dharambir Singh will speak.

श्री धर्मबीर सिंह (बाढ़ड़ा) : स्पीकर सर, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में पढ़ा था और सुरजेवाला जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है मैं उस पर हो रही चर्चा में हिस्सा

लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर सर, इस सरकार को बने अभी 16-17 दिन ही हुए हैं। हमारी आदरणीय नेता सोनिया जी ने हरियाणा में एक बहुत ही ईमानदार नेता को मुख्यमंत्री बनाया है। पिछली सरकार के वक्त में हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार में बिहार और यूपी से भी ऊपर आ गया था लेकिन इस सरकार ने इन 16-17 दिनों में जो निर्णय लिए हैं उससे प्रदेश के लोगों में विश्वास जागा है कि हरियाणा में जितनी बीमारियां लग गई थीं वह अब दूर हो जाएंगी। हुड्डा साहब, हमारे नेता हैं। इन 16 दिनों में उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं चाहे उन निर्णयों में आईपीएस और आईओएस आफिसर की बदलियां की हैं दूसरे अच्छे निर्णय लिए हैं उससे हरियाणा के लोगों में विश्वास जागा है कि हरियाणा में जो भ्रष्टाचार फैल गया था, अब उस पर अंकुश लग जाएगा। स्पीकर सर, सोनिया जी की अध्यक्षता में हरियाणा के इलेक्शन मैनीफैस्टो में चुनाव से पहले जो घोषणाएं की थीं, उनको 100 प्रतिशत लागू करने की कोशिश की गई है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अगर सबसे ज्यादा ध्यान किसी बात पर दिया है तो वह यह है कि उन्होंने अनुभवी आदमियों को और ईमानदार आदमियों को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। अध्यक्ष महोदय, 70 प्रतिशत से ज्यादा हमारे प्रदेश की जनता कृषि पर निर्भर है। आज का दक्षिणी हरियाणा पिछले कई सालों से इस बात के लिए संघर्ष कर रहा था कि हमें भी बाकी हरियाणा के बराबर पानी दिया जाए क्योंकि हरियाणा में इस साइड में पानी नहीं था। अध्यक्ष महोदय, आज भी सौ से भी ज्यादा गांव ऐसे हैं

जहां पीने का पानी नहीं है और जहां पर वाटर लेवल भी बहुत कम हो चुका है। पहले हमें यह कहकर बहकाया जाता था कि जब एस0वाई0एल0 कैनल बन जाएगी तो रावी व्यास का पानी आपको मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता को यह चाहती थी कि जो पानी सतलुज और ब्यास का अभी तक हमें मिलता है उसमें से तो उनको पूरा हिस्सा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का कुछ इलाका तो ऐसा है जहां दस मिनट में एक किल्ला भर जाता है और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर एक महीने तक पानी नहीं आता था और अगर पानी आता भी था तो कह दिया जाता था कि आपको केवल पीने का पानी ही मिलेगा खेती का नहीं। मौजूदा सरकार ने बनते ही नहरी पानी का बराबर समान बंटवारा करने का फैसला लिया है, यह एक स्वागत योग्य बात है। सरकार के इस फैसले का स्वागत सारी हरियाणा प्रदेश की जनता ने ही नहीं बल्कि इस हाउस के एम0एल0एल0 ने भी किया है। अभी हमारे सामने बैठे विधायक डा0 सीताराम जी ने भी यह कहने की कोशिश की कि उनकी सरकार बनने से पहले भी इस बारे में गलत काम हो रहे थे इसलिए अगर पानी का बंटवारा समान रूप से किया जाता है तो वे भी इसमें शामिल हैं और यह बंटवारा ठीक किया ही जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सारा हाउस इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी है। गवर्नर महोदय ने भी अपने अभिभाषण में यह बात स्पष्ट कर दी है कि प्रदेश के पानी का बंटवारा समान रूप से होगा। अध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या के बाद एक समस्या बिजली की भी है। पिछली सरकार ने स्लैब

प्रणाली खत्म की थी और यह सिस्टम करने की कोशिश की कि जहां पर पानी 25 फुट गहरा है और जहां पर 6 इंच की पानी की निकासी थी वहां पर भी वही रेट लिए जाएंगे और जहां पर पानी चार सौ फुट गहरा है और बीस होर्स पावर की मोटर लगाने के बाद भी केवल दो इंच ही पानी निकलाता है वहां पर भी वही रेट लिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी स्लैब प्रणाली जरूर शुरू करें ताकि पैसा बराबर देकर बराबर पानी निकाला जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सरकार ने आते ही यह भी निर्णय लिया कि कुदरत की मार पड़ने पर जैसे ओलावृष्टि आदि होने पर उनकी फसलों के खराब होने की स्थिति में पचास परसेंट ज्यादा मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो लोग ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं तो मैं चाहूंगा कि इस तरह का पैसा जमीन मालिक के बजाय खेती करने वाले को मिलना चाहिए। जहां पानी का समान बंटवारा है वहां पर हर माइनर और हर नहर पूरे सात दिन तक चलनी चाहिए। जहां पर पम्प हाउसिज खराब है उनको भी सुधारा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज से बीस-बाईस साल पहले शायद उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, के वक्त में स्प्रिंकलर सैट्स खरीदे गए थे लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनमें से तकरीबन पचास परसेंट स्प्रिंकलर सैट्स पिछली सरकार ने बगैर यूज किए थोड़े पैसों में कहीं बेच दिये या ट्रांसफर कर दिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्प्रिंकलर सैट्स खरीदकर महेन्द्रगढ़ और भिवानी के इलाकों में चालू किए जाएं ताकि कम पैसों से

ज्यादा सिंचाई हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी नहरें हैं खासकर जितने फीडर हैं उनमें डायरेक्ट आउटलैट लगे हुए हैं। मेरा सिंचाई मंत्री से अनुरोध है कि किसी भी क्षेत्र में अगर इस तरह के डायरेक्ट आउटलैट फीडर लगे हुए हैं तो वे सभी आउटलैट फीडर से उखाड़े जाएं। इसी प्रकार से कृषि के मामले में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सरसों की फसल आ चुकी है। भारत सरकार ने इसके रेट फिक्स कर रखे हैं लेकिन इसके जो रेट तय किये गये हैं उस रेट पर सरकारी एजेंसीज सरसों की खरीद नहीं कर रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि पिछली सरकारों की तरह बिचौलिए अपने आदमियों की सरसों खरीद लें और दूसरे आदमियों की न खरीदें। मेरी मांग है कि सरसों की खरीद के सिस्टम को भी सुधारा जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने माइनिंग के बारे में एक मिनट में फैसला लिया कि अवैध नाके बंद हों। सारे प्रदेश में पिछली सरकार ने जो गलत काम किए थे अब वह बर्दाश्त नहीं होंगे। इस बारे में मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश की जनता का पैसा गलत तरीके से वसूला था चाहे वह टैक्स के रूप में वसूला हो, चाहे किसी भी तरीके से वसूला हो। पिछले पांच साल में इन्होंने माइनिंग के ऊपर बैठकर जो पैसा वसूला है उसकी इंकवायरी करवाकर पैसा जरूर वापस दिलवाया जाए। इसी प्रकार से एजुकेशन के मामले में मैं मानता हूँ कि हर जगह सरकार अपने कालेज नहीं चला सकती लेकिन प्राइवेट कालेज खोलने के लिए

हमारे पास बड़े-बड़े उद्योगपति भी हैं जो प्रदेश से बाहर गए हुए हैं उनसे भी लाइजनिंग की जा सकती है उनसे कहकर प्राइवेट कालेज चालू करवाए जाएं। पब्लिक ने मिलकर बाढ़ड़ा में कालेज बनवाया है उसकी भी स्वीकृति दे जहां जहां स्टाफ की कमी है चाहे तोशाम में या भिवानी का आदर्श कालेज है इनकी बिल्डिंग बनी हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं पिछली सरकार ऑब्जेक्शन लगा देती थी कि फंड्स की कमी है। एक-एक कालेज में 20-20 लैक्चरर थोड़े से पैसे पर रखे जाते हैं लैक्चर्स की स्वीकृति सरकार दे ताकि वहां के बच्चों को पढ़ने की सहूलियत हो जाए। (विधन) मैं ज्यादा समय लेते हुए आपका धन्यवाद रते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सुरजेवाला जी ने गवर्नर साहब के एड्रेस को पास करवाने के लिए सभी चीजों के बारे में पूरी रोशनी डालने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं कुछ ही बातें कहना चाहूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से आने वाले पांच साल की अपनी नीतियों को सामने रखा है सदन के सामने रखा है और सदन के माध्यम से जनता के सामने रखा है। अध्यक्ष महोदय, भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन यानी ये चीजें सुनने वाले हर व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन स्पीकर सर, यह बहुत ही कठिन काम है। बड़ा भारी चैलेंजिंग टास्क है। हमारी सरकार की जो मशीनरी है उसको

पिछले पांच सालों में न सिर्फ जंग लगा दिया गया बल्कि इसको गला दिया है। आज भी ऐसे उच्चाधिकारी जो भ्रष्टाचार में तथा क्राइम में टोटली इन्वोल्व थे, ऐसे अधिकारियों का अभी भी फील्ड में कोई न कोई रोल रहेगा, इसका मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे ऊपर बेशुमार नाजायज मुकदमे बनाए गए, कत्ल के मुकदमे इतनी सरलता से बनाए, उन उच्चाधिकारियों से जब तक आप सवाल जवाब नहीं करेंगे और जब तक उनको सजा नहीं देंगे, जब तक ऐसा वातावरण नहीं बनाएंगे कि किसी उच्चाधिकारी को इस प्रकार का खिलवाड़ करने की मजाल नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक वे खिलवाड़ करने से बाज नहीं आएंगे।

15.00 बजे

ऐसे ऐसे अधिकारी रहे हैं कि दरखास्त एस0पी0 को लिखी हुई है और उसके ऊपर आदेश डी0सी0 दे रहे हैं। 302 के मुकदमे बनाये और कोर्टस के फैसले में यह कहा गया Prosecution should be ashamed of framing such charges where there is no evidence.

And we have suffered for 3 years. In my case I was booked under a case under Section 302 in which there was no evidence. And I was going to the Court up and down for three long years. Finally, the prosecution could not produce any evidence against me and we were acquitted honourably. स्पीकर सर, पहले ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने लोगों के साथ न सिर्फ

खिलवाड़ किया हो बल्कि ऐसे भी अधिकारी रहे हैं जिन्होंने जनता के प्रतिनिधियों से भी उनकी शान में गुस्ताखी की और उन्हें फिजीकली असाट किया। मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अर्ज है कि ऐसे व्यक्ति को सजा जरूर दी जाए। यह संभव है कि इस बारे में काफी सिफारिशें भी आएंगी और जातिवाद व रिश्तेदारियों की बात भी आएगी। अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसे अधिकारियों को बखशा जाता है तो वह जनता के साथ खिलवाड़ होगा। पिछले शासन में ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारी भी रहे हैं जिन्होंने लोगों को अगवा करवाया। एक मुलजिम जो बहुत अर्से बाद पकड़ा गया था। वहीं घूमता रहा और सुनते हैं कि वह काफी समय तक चौटाला में रहा और काफी अर्से बाद आखिरकार पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसने प्रैस में यह स्टेटमेंट दी कि मैंने एक सेठ के लड़के को 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए पकड़ा था और उस काम में मेरा सहयोग कैथल के एस0एस0पी0, एक इंस्पैक्टर और दूसरे अधिकारियों ने दिया था। उसके बाद उस अपराधी को चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने इनाम में मैडल भी दिया। ऐसे भी व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने किसानों को भूना है और जो अब भी खुले आम घूम रहे हैं। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार में ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने किसानों को परेशान किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम किसानों और मजदूरों की लड़ाई उनकी अध्यक्षता में लड़ते थे तब इन्होंने किसानों को यह वचन दिया था कि अगर उनकी सरकार आयेगी तो वे ऐसे अधिकारियों को माफ

नहीं करेंगे। लेकिन आज वही अधिकारी अगर महत्वपूर्ण जगहों पर लगे रहेंगे तो वे सरकार में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बलड़ी गांव में एक नौजवान का कत्ल किया था और बाद में उसको मुठभेड़ दिखाया था।

स्पीकर सर, बहुत ही अच्छी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है कि वे भय मुक्त और भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देंगे। माननीय मुख्यमंत्री बनते ही कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए काफी एक्सरसाईज की है। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति सरकार के अन्दर अब भी मौजूद हैं उच्च प्रणाली में, ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं जो कांग्रेस की पिछली सरकार के समय में भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, गबन के केस में सस्पेंड थे, ऐसे –ऐसे आई०ए०एस० अधिकारी जो पांच साल तक सस्पेंड रहे और जैसे ही सरकार का परिवर्तन हुआ जिन्होंने भ्रष्टाचार की मिसाल कायम की हुई थी वे अधिकारी भी अच्छी पोस्टिंग पाने में कामयाब हुए। जिन लोगों ने उनको भ्रष्टाचार के मामले में पकड़वाया था उनसे बदला लेने में वे कामयाब हुए। इन सारी चीजों का आप जायजा लें और मुझे आशा और विश्वास है कि आपने उपयुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का जो लोगों से वायदा किया था, उसे आप पूरा करेंगे।

इस अभिभाषण में खेती के बारे में चिन्ताजनक बात का जिक्र करते हुए बहुत से सुझाव आये हैं। यहां पर क्रोप

डाइवर्सिफिकेशन की बात भी की गई है श्री सुरेन्द्र सिंह जी, जो हमारे बीच बैठे हुए हैं उन्होंने क्रोप डाइवर्सिफिकेशन की बात की है। इस बारे में हम बहुत ही मुद्दत से सुनते आ रहे हैं कि क्रोप डाइवर्सिफिकेशन हो। तरह-तरह के बड़े-बड़े प्रतिनिधि मण्डल इस मामले में विदेशों में भी गए। ग्रीन हाउस की प्रणाली बनाई गई, ड्रिप इरीगेशन की योजना बनाई गई, स्प्रिंकलर सैट्स की योजना बनाई गई लेकिन अब तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों में किसानों का मण्डियों में शोषण हुआ है और इसकी एवज में पिछले मुख्यमंत्री और उनकेहासिल की है।के माध्यम से किसान की जीरी 100 रुपए प्रति क्विंटल कम बिकी थी क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करते थे और जेलों में जाते थे और सरकार का ध्यान आकर्षित करते थे। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से वह अन्धी और बहरी सरकार और एक भ्रष्ट सरकार होने की वजह से उसने किसानों का खून निचोड़ा था। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे ताकि भविष्य में किसानों का शोषण न हो। आज एम0एस0पी0 के बारे में अखबार में एक खबर थी कि सरसों की फसल मिनिमस स्पोर्ट प्राइज से कम बिक रही है, यह बात आपके नोटिस में आ गई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इन सारी बातों पर ध्यान देगी। हम यह बात भी बार-बार करते हैं और सुरजेवाला जी ने भी कही है कि कम सूद पर किसान को ऋण मिलना चाहिए, हमारी यह मांग सदा से ही हो

रही है। किसान का काम केवल ऋण लेने से चलने वाला नहीं है। आज हमारी भूमि की जोत बहुत छोटी हो गई है जिसकी वजह से आज कृषि करना न सिर्फ अनइक्लोमिकल है बल्कि उसके ऊपर निर्भर रहने से तो अच्छा मजदूरी कर लेना है। हमारी प्रति एकड़ आमदन क्या हो इसका निर्णय दिल्ली की सरकार करती है पिछले 5 सालों के संघर्ष का जो जीवन हमने बिताया है उसमें हम बार-बार एक चीज के ऊपर जोर देते रहे कि किसान को अच्छी मिनिमम स्पॉट प्राइज हम दिलवाएंगे। आज सौभाग्य से आप लोगों के लिए जहां भी कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए गेहूं, जीरी, कपास, गन्ने और अन्य सभी फसलों का किसान को अच्छा मूल्य उपलब्ध करवाने की कोशिश करें। ऋण लेना सुविधा तो है लेकिन यह लोन लेना कोई मीन्स नहीं है। ऋण लेना जिंदगी बिताने के लिए कुछ हद तक ही उचित है। दिल्ली में बातें होती हैं कि हमने ऋण देने की सीमा को इतना बढ़ा दिया सूद को कम करने की मांग तो जायज है लेकिन ऋण की सीमा रेखा को ज्यादा बढ़ाना मैं समझता हूं कि बोझ को बढ़ाना है। अध्यक्ष महोदय, लोगों को काम देने के हमें नए तरीके ढूंढने होंगे और गांव के अंदर कोटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना होगा। कोटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए मार्किटिंग की भी बड़ी आवश्यकता है। एक छोटा किसान, गरीब आदमी, एक दलित, एक गांव का कुम्हार अपनी बनी चीजों को मार्किट में कहीं बेच नहीं सकता, इसलिए उनके लिए सरकार को

कहीं न कहीं मार्किटिंग प्रणाली को बनाना होगा। जब कांग्रेस की पिछली सरकार थी, तब इस बारे में एक बड़ी भारी योजना कुण्डली में बनाई गई थी। उस योजना के अंदर डायवर्सिफिकेशन का एक नजरिया था, डायवर्सिफिकेशन के लिए वहां फूलों के लिए, तिलहन के लिए और दूसरी चीजों की मार्किटिंग के लिए प्रावधान किया गया था लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है बड़ी सरलता के साथ उस सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर को पिछली सरकार ने HSIDC और दूसरी संस्थाओं को दे दिया।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, अब आप जल्दी वाइंड अप करें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, आपने औरों को 15-15 मिनट बोलने का समय दिया है मुझे तो बोलते हुए अभी 5 मिनट ही हुए हैं, मेरी तो अभी लय ही बनी है और आप मुझे वाइंड अप करने के लिए कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं यूनिवर्सिटीज की बाबत कुछ कहना चाहूंगा और सुरजेवाला जी ने भी इसके बारे में कहा था। यूनिवर्सिटी में कार्य करने वाले एक क्लर्क को वहां का सभापति बनाया गया और बाद में उसे वाइस चांसलर बनाया गया यह बड़े दुख की बात है। इस प्रकार के पदों पर काय्र करने के लिए तो बड़े विशेषज्ञ होने चाहिए। 5 साल से किसी यूनिवर्सिटी ने किसी क्राप का नया बीज नहीं निकाला यह बड़े अफसोस की बात है। हमारी हिसार यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं लेकिन वह यूनिवर्सिटीआज

बनकर रह गई है। सैकड़ों आदमी हिसार यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बाहर से आते हैं ऐसा सुनने में और देखने में आया है कि लोग वहां पर जबरदस्ती खाना खा करके चले जाते हैं। मुझे यकीन है सरकार के परिवर्तन के बाद वहां के वातावरण में जरूर बदलाव आया है लेकिन इस बदलाव को बनाए रखने के लिए सख्त निगाहें रखनी पड़ेंगी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को स्वच्छ वातावरण देने के लिए पोल्यूशन बोर्ड लगाया गया है और इस बोर्ड की कार्यप्रणाली को मैं 20-20 सालों से देखता आ रहा हूं। इंडस्ट्रीज वालों को एक बहुत छोटी सी रकम अपना पोल्यूशन यंत्र लगाने के लिए पोल्यूशन बोर्ड को देनी पड़ती थी। लेकिन पिछली सरकार ने 5 सालों में इस पोल्यूशन बोर्ड को प्रदेश से पोल्यूशन दूर करने के बजाय अपने सियासी विरोधियों को काटने के लिए एक यंत्र बनाया था। मेरी अपनी एक छोटी सी पेपर मिल है यह मिल पोल्यूशन के सारे पैरामीटर्स पूरे करती थी लेकिन फिर भी 300 सिपाहियों को ऊपर चढ़ाकर उसके अन्दर ताले लगवा दिए गए और कहा गया कि इससे दूषित पानी जाता है। दुर्भाग्य से 300-400 परिवार जो इस मिल से अपनी रोजी-रोटी कमाते थे वे परिवार अपनी रोजी रोटी कमाने से वंचित हो जाए। मैं चाहूंगा कि इस पोल्यूशन बोर्ड का सही इस्तेमाल किया जाए। यही नहीं हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हमारे अरोड़ा साहब ने जो ब्यान दिया है वह स्वागत योग्य है। हमें खुशी है कि इन्होंने बाहर के उद्योगपतियों को हरियाणा में उद्योग लगाने का न्यौता दिया है। अब इस सरकार के बनने के बाद बाहर के उद्योगपति प्रदेश में

इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आने को तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, हम दिल्ली के तीन तरफ हैं और उद्योग लगाने की यहां सुविधा भी है। मैं अरोड़ा साहब से कहना चाहूंगा कि केवल न्यौता देने से काम नहीं चलेगा बल्कि आप सभी इण्डस्ट्रियलिस्ट्स की मीटिंग बुलायें और उनके अन्दर विश्वास कायम करें। यह जो लैंड यूज का दुरुपयोग होता रहा है इसको भी सस्ता करिये। उद्योगपति आम किसानों की लैंड तो तभी खरीदेंगे जब लैंड यूज का पैसा आप कम लगाएंगे तभी देहात में इण्डस्ट्री आयेगी वरना तो इण्डस्ट्री स्टेट से बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम यह चाहेंगे कि आप गांवों में, बैकवर्ड इलाकों में इण्डस्ट्री लगाने की सुविधाएं दें और लैंड यूज का जो जुर्माना है, जो उसका खर्चा है वह कम से कम हो। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे बहुत बड़े उद्योगपति जिंदल साहब बिजली मंत्री बने हुए हैं। इनका बिजली उत्पादन का अपना बहुत बड़ा कारखाना है और मुझे मालूम है कि इनको बिजली उत्पादन का बहुत अनुभव है। ये अपने कारखाने में बहुत योगदान देते हैं। इसमें मुश्किल यह है कि सरकार की अवधि पांच साल है और बिजली उत्पादन का प्लांट लगने में 8-10 साल का समय लगता है। छोटी और बड़ी योजनाओं में जब तक संतुलन नहीं होगा, तब तक काम चलने वाला नहीं। जैनरेटिंग सैट्स पर, कैपेटिंग पावर पर और दूसरी चीजों पर जब तक सरकार सरलता से सबसिडी नहीं देगी तब तक यह जो बिजली की कमी है वह दूर नहीं होगी। ये सुविधाएं किसानों को भी दी जानी चाहिए ताकि किसान भी अपने

छोटे-छोटे जैनरेटिंग सैट्स लगा सकें और इण्डस्ट्रीज अपने जैनरेटिंग सैट्स अलग से लगा सकें। मुझे मालूम है कि इण्डस्ट्रीज के लिए लोन लेने के लिए लोग दस-दस, बारह-बारह साल से लाइन में लगे होते हैं फिर भी उनको लोन आसानी से नहीं मिलता। यदि काफी समय के बाद दो-दो चार-चार लाख रुपए मिलते भी हैं तो इसके लिए भी उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। लोन लेने वालों की एप्लीकेशन पर इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए दो-दो चार-चार लाख रुपए भी लोन के नहीं मिलते। रिश्वत भी देनी पड़ती है फिर आखिर में लाईन फेर दी जाती है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं पैसा नहीं दिया जाएगा। पिछली सरकार के समय में ऐसा मजाक उद्योगपतियों के साथ होता था। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी व्यवस्था को हमें बदलना होगा। स्पीकर सर, गरीब आदमियों को पेंशन देने की कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। पिछली सरकार के समय में हरिजन, वाल्मीकि, दलित समाज पिछड़े वर्ग और गरीब आदमी पेंशन से वंचित रहे हैं मुझे यह पर्सनल नालेज है कि जैसे कैथल जिले में 18 हजार नये पेंशन के केसिज बने, ऊपर से आदेश आया कि इनको 9 हजार रखो, उसके बाद फिर आदेश आया कि 4 हजार रखो और दुर्भाग्य से उन 4 हजार में भी गरीब आदमियों को पेंशन नहीं मिली। जो मलंग थे ढींग थे वे पेंशन ले गये। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि पेंशन का सर्वे दोबारा से करवाया जाए और जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको अधिकार दिया जाये कि वे अपने-अपने क्षेत्र के

गरीब आदमियों को, बुजुर्गों को, माताओं को, विधवाओं को पेंशन दिलवाने में सक्षम रहें। इसी प्रकार से गुलाबी और पीले कार्डों की भी भारी समस्या है। हम प्रचार के दौरान संघर्ष के दौरान कहते रहे हैं कि पिछली सरकार में बहुत भेदभाव हुए हैं और मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री जी भी इस बात से अवगत हैं इसलिए इस सर्वे को भी दोबारा से करवाया जाये तथा सर्वे करवाने से पहले गरीबी की लाइन को भी ऊपर करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो गरीब लोग हैं वे और गरीबी में धंसते चले जा रहे हैं, लोगों को हमें सुविधाएं देनी होंगी। एक तरफ किसानों को उनके जिन्स के दाम देने होंगे दूसरी तरफ हर जाति के गरीब लोगों को विशेषकर दलितों को, बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को अन्य सुविधाएं देनी होंगी। हमें उनको सस्ती चीनी और अनाज की सुविधा देनी होगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी सरकार में रहने का मौका मिला। मेरे पास आई०टी०आई विभाग था, आई०टी०आई० विभाग में मैंने बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन पैदा किया था। मैंने आई०टी०आई० विभाग के अंदर उन सब इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज को इन्वोल्व किया था जो हमारे बच्चों को बाद में नौकरियां दती थी। लेकिन बाद की सरकारों ने मेरी वह प्रथा बदल दी। मैं फूलचन्द मुलाना जी से प्रार्थना करूंगा कि जितनी इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज हरियाणा में हैं उन सबमें एक-एक, दो-दो आई०टी०आई० को इन्वोल्व करें। जैसे फरीदाबाद में, करनाल में, गुडगांव में और यमुनानगर आदि कई जगहों पर इस तरह की इण्डस्ट्रीज हैं। करनाल में तो हमारा लिबर्टी ग्रुप है। वहां पर

विशेषकर हमारे दलितों के लिए एक नई प्रणाली इस प्रकार की बन सकती है। जिसके तहत उन्हें रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ओल्ड ऐज होमज की बात करना चाहूंगा। हमारे गांवों में दो-दो कमरों के मकान ओल्ड ऐज होमज के नाम पर बना तो रखे हैं लेकिन उनमें सूअर पलते हैं। वहां कोई ओल्ड ऐज होम का प्रावधान नहीं है। मैं चाहूंगा कि ओल्ड ऐज होमज की जिम्मेवारी सोशल संस्थाओं को दी जानी चाहिए और सरकार उन संस्थाओं को वित्तीय सहायक देकर मदद करे। हमारे यहां बहुत से गुरुकुल और दूसरी संस्थाएं हैं जो उन्हें लेना चाहती हैं। इन सभी बातों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए इसका अनुमोदन करता हूं और सरकार को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री शादीलाल बतरा (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता की दूरदर्शिता पर, उसकी पोलिटिकल मेच्योरिटी पर और उसके पिछले इलैक्शन में लिए गए निर्णय के लिए शत-शत नमस्कार करके उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से आतंकवादी और भ्रष्टाचारी सरकार को चलता किया। लोगों ने अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए जो सपने संजोये थे उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की सरकार चुनी है। मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी एक निष्ठावान, ईमानदार और एक सच्चे

सेवक को इस प्रदेश का मुखिया बना कर हमें और इस विधानसभा में उनके नेतृत्व में काम करने का एक मौका दिया है। इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार केवल भ्रष्टाचार से चली। यह भ्रष्टाचार सिर्फ जनता में ही नहीं था बल्कि सरकार में भी था। जब पिछली बार बजट पेश किया गया तो उस वक्त सिर्फ 1471 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था जबकि बाद में जाकर वह घाटा 2923 करोड़ पर खत्म हुआ। यह पिछली सरकार 1999 में आई थी और 2005 तक रही। जब तक सरकार ने सत्ता संभाली थी तो उस वक्त 12249 करोड़ रुपए के लोन सरकार पर थे जो उनके समय में बढ़कर 22194 करोड़ रुपए हो गए यानि वे इतने रुपये लोन के छोड़ कर गए हैं। इस लोन पर जा इन्ट्रैस्ट लगता है उसमें भी 56 परसेंट की वृद्धि हो गई। पिछली सरकार ने 2002-03 में 172 करोड़ 59 लाख रुपए ऐसे खर्च किए जिनकी पहले कोई मन्जूरी नहीं ली गई और न ही उस खर्चे का कोई प्रावधान था। वह सरकार सरकारी बजट को इस प्रकार खर्च करती थी और सरकारी कोष को इस तरह लूटती थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की जनता ने उसको चलता किया। इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उस वक्त की सरकार ने जब सत्ता संभाली तो एरियर्ज आफ रवैन्यू 312 करोड़ रुपए के थे और वे जाते हुए एरियर्ज आफ रवैन्यू के 851 करोड़ रुपए छोड़ करके गए हैं। ऐसी सरकार के मुखिया ऐसी दिमागी बीमारी से ग्रस्त थे जिसका कोई हिसाब नहीं है। वे कहते

थे कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसी कुर्सी पर बैठा रहूंगा। मेरी आखिरी सांस तक मेरी सरकार चलेगी। सरकार का डर इतना था कि कोई बोलता नहीं था। उस वक्त की सरकार का सिवाये आतंक और भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा की कि हम अत्याचार और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार प्रदेश को देंगे। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई है। कहते हैं कि इस सरकार की उम्र आज केवल 17 दिनों की है। इन 17 दिनों में इस सरकार ने जितने अच्छे फैसले लिए हैं वे आपके सामने हैं और जो फैसले लिए गए हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा नहीं तो आप कहेंगे कि समय समाप्त हो गया। मुझे इसमें एक बात नजर आती है कि इस मौजूदा सरकार का हर फैसला जनता ने सराहा है और अब सभी वर्ग के लोग खुश हैं। चाहे सरकारी कर्मचारी है या व्यापारी है सभी ने यही कहा है कि यह नई सरकार जिस ढंग से चल रही है वह बहुत सराहनीय है। यह हमारी सरकार चलते-चलते उस दिशा में और उस मंजिल पर पहुंचेगी जिस मंजिल पर हरियाणावासियों ने अपने सपने संजो रखे हैं। चाहे वे सपने सुरक्षा के हैं और चाहे वे सपने विकास के हों सभी सपने पूरे होंगे। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी आफिसर्ज आए हैं उन आफिसर्ज पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रशासन में निष्ठावान और ईमानदार छवि के जो व्यक्ति आए हैं उनसे हमें विश्वास भी है कि अब तब जो व्यक्ति आए हैं वे जनता की सेवा करने के लिए आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं शिक्षा की नीति पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। पिछली सरकार की शिक्षा की नीति क्या थी वह सभी को पता है। उनकी सरकार में शिक्षा इतनी महंगी हो गई थी जिनका कोई हिसाब नहीं है। उनके समय में किसी गरीब का बेटा डाक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए सोच नहीं सकता था चाहे उसमें कितने ही अच्छे गुण हों। अगर उसके बाप के पास पैसा नहीं था तो वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। जो कालेजिज हैं उनमें सरकार की तरफ से ग्रांट मिलती है। अगर कालेज के किसी विभाग के लैक्चरर की भगवान न करे, डैथ हो जाए तो उसके बदले उसके परिवार के दूसरे व्यक्ति को नौकरी में लेने की जो मंजूरी थी वह भी उन्होंने समाप्त कर दी। इतना ही नहीं यदि किसी लैक्चरर की रिटायरमेंट हो जाती है तो उसके बाद दूसरा लैक्चरर भी नहीं रखते थे क्योंकि वे इसका खर्चा वहन नहीं कर पाते थे। इससे नुकसान किसी और का नहीं केवल बच्चों का होता था। आज शिक्षा संस्थानों में बहुत स्थान रिक्त पड़े हैं। पहले इन रिक्त स्थानों की भर्ती करने के लिए सरकार की तरफ से मन्जूरी नहीं मिलती थी। ऐसी सरकार जो शिक्षा पर आघात करे, जो यह चाहे कि हरियाणा के बच्चे पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त न कर सकें और हरियाणा के बच्चे अपने आप को पूरा विकसित न कर सकें तो ऐसी सरकार का क्या फायदा था? शिक्षा के बारे में अब हमारी सरकार की ऐसी सोच नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीति ऐसी नहीं है। हमारी सरकार की सोच यह है कि हमने जो शिक्षा देनी है वह

सस्ती होनी चाहिए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए और उसके द्वारा हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए। सरकार का पहला दायित्व यह होता है कि प्रदेश की जो जनता है उस के हर हाथ को काम मिलना चाहिए ताकि वे समाज की मुख्य धारा का अभिन्न अंग बन कर रहें और मुख्य धारा से विमुख न हों। मुख्य धारा से विमुख न होने के लिए यह जरूरी है कि उनकी आर्थिक पोजिशन ऐसी हो कि उनके परिवार की पालना ठीक से हो सके और वे लोग अपने तथा अपने परिवार की पालना ठीक तरह से कर सकें। पिछली सरकार ने क्या किया, जिन लोगों की अलग-अलग महकमों में 25-25, 30-30 साल की सर्विस थी वे डिपार्टमेंट बन्द कर दिए। एम0आई0टी0सी0 का डिपार्टमेंट ठीक प्रकार से काम कर रहा था और उसमें लोगों को रोजगार भी मिला हुआ था। ऐसा नहीं था कि एम0आई0टी0सी0 का कार्य खत्म हो गया था, कार्य चल रहे थे लेकिन कार्यों के चलने के बावजूद उन्होंने डिपार्टमेंट खत्म कर दिया। अगर डिपार्टमेंट को खत्म भी करना था तो एम0आई0टी0सी0 के जितने भी कर्मचारी थे उनका कोई वैकल्पिक प्रावधान करना चाहिए था। किसी और डिपार्टमेंट में उन कर्मचारियों को लगाया जाना चाहिए था या उनको ऐसे साधन बनाकर देने चाहिए थे जिससे वे अपना गुजारा कर सकें। एम0आई0टी0सी0 के कर्मचारी हजारों की संख्या में हैं और वे आज सड़कों पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय आप कभी भी देखें, मुझे तो ऐसे कई परिवारों को देखने का मौका मिला है। कई लोगों की 30-30 साल की नौकरी हो गई थी लेकिन अब नौकरी से निकाल

देने के बाद अब उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। वे लोग अपने घरों में खाली बैठे हैं और परेशानी में आत्महत्या करने की सोचने लग गए हैं। ऐसी सरकार का क्या करें जो रोजगार देने के बजाय रोजगार छीने। आज लोग इस सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे यह सोचते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ ऐसा कार्य करेगी जिससे हरियाणा का हर बच्चा, हर वासी खुश होगा और गर्व से कह सकेगा कि यह हरियाणावासी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अब जमीनें बहुत थोड़ी हो गई हैं। इसलिए अब प्रदेश में इण्डस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। जब इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो तो एनसिलरीज लगेगी और उन बच्चों को जो नौजवान हो चुके हैं, अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं, रोजगार का कोई न कोई साधन मिल जाएगा। उनको कहीं पर नौकरी मिल जाएगी जिससे वे अपना गुजारा कर सकेंगे और आने वाले बच्चों का लालन-पालन बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से कहूंगा कि यहां पर इण्डस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। रोहतक में कोई बड़ी इण्डस्ट्री नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई न कोई ऐसी मदर इण्डस्ट्री वहां पर लगाई जाए जिससे वहां के बच्चों को रोजगार मिल सके। मदर इण्डस्ट्री लगने के बाद उसकी एनसिलरीज भी आएगी और दूसरी चीजें भी आएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, विकास के मामले में हमारा रोहतक भेदभाव का शिकार हो रहा है और आज किसान की दशा ऐसी है कि हम कह सकते हैं कि गांव के लोग भी उससे अच्छे तरीके से रहते हैं। यहां पर

पानी की बड़ी भारी प्राब्लम है। 1966 में हरियाणा बना था। हरियाणा बनने के बाद आज 1966 से 2005 हो गया है लेकिन हमारे लोगों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि उसको पीने का पानी मिले लेकिन पानी की बहुत ही कमी है। वहां पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है वह इतना गंदा मिल रहा है कि जैसे सीवर का पानी हो। सीवर और पीने के पानी की लाइनें आपस में मिली हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि रोहतक के लोगों को यह मौलिक अधिकार मिलना चाहिए और उनको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। स्वच्छ पानी के लिए ऐसी स्कीम बनाएं कि जब बजट आए तो बजट में उसका प्रावधान हो ताकि हम उस प्रावधान के नाते जनता से इतना कह सकें कि पीने का पानी मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही सीवर की समस्या है। कहने को तो रोहतक शहर है और शहर में कहीं कोई खाली जगह नहीं होती है। हमारी मां बेटियां सवेरे शौचालय के लिए जाएं तो कहां जाएं? अगर उनके घर में सीवर नहीं हैं तो उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। उनको कितनी दुर्दशा का सामना करना पड़ता है यह भी सोचने वाली बात है। हम चाहते हैं कि हर गली और हर मौहल्ले में सीवर की समस्या का समाधान होना चाहिए। जब सड़क की बात आती है तो रोहतक शहर में सड़कों का तो कहीं पर नाम भी नहीं है। सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। अगर कोई मोबिलिटी नहीं है तो फिर कैसा विकास? मैंने

पिछली बार यहां आन दि फलोर ऑफ दि हाउस भी सड़कों की दशा सुधारने के लिए कहा था और सरकार ने मुझे आश्वासन भी दिया था लेकिन वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक मुझे कोरे आश्वासन ही मिलते रहे लेकिन उन आश्वासनों पर कभी अमल नहीं हुआ। वे सड़कें कभी नहीं बनी। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि वे सड़कें जो पिछली सरकार ने जानबूझ कर नहीं बनाई थी और रोहतक के लोगों से यह कहा था कि आप लोगों ने जब हमारी सरकार को वोट नहीं दिया तो हम आपको सड़कें बनाकर क्यों दें? मेरा इस बारे में सरकार से अनुरोध है कि रोहतक शहर की सड़कों को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री किसी एक जिले के मुख्यमंत्री नहीं थे बल्कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी को एक आंख से देखना चाहिए था और सभी को सद्भावना के साथ देखना चाहिए था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री यह कहे कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है क्योंकि इन्होंने हमें वोट नहीं दिए थे। उपाध्यक्ष महोदय, आज लोगों की आशाओं के मुताबिक बनी हुई सरकार हरियाणा प्रदेश में आई है। उपाध्यक्ष महोदय, रोहतक में बस स्टैंड को पुरानी जगह से उठाकर बाहर ले जाने का काम किया गया था। बस स्टैंड कहीं पर भी चला जाए कोई बात नहीं लेकिन आज व्यापारी को, आम आदमी को, मजदूर को उस बस स्टैंड तक जाने के लिए रिक्शा के इतने पैसे देने पड़ते हैं जितने उसके बस स्टैंड से अपने जगह पर जाने के

लिए भी नहीं लगते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि दूसरी जगहों पर जाने के लिए बस स्टैंड चाहे वहीं पर रहने दिया जाए लेकिन लोकल बसिज को पुराने अड्डे से ही चलाने का प्रबन्ध किया जाए। अगर वहां से बसें चलेंगी तो आम आदमी को, मजदूरों को और व्यापारियों को फायदा होगा और वे आराम से शहर में आ जा सकेंगे। बाहर से आए हुए लोग शहर के अन्दर आकर सामान वगैरह खरीदेंगे जिसकी वजह से वहां के लोकल आदमियों को और व्यापारियों को आमदनी होगी और फायदा होगा। इसलिए मेरा सरार से पुनः निवेदन है कि वहां पर पुराने बस स्टैंड और नए बस स्टैंड के बीच लोकल बसें चलानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पोल्यूशन के बारे में कहना चाहता हूँ। आज शहर पोल्यूशन का अड्डा बन गया है। वहां पर जो थ्री-व्हीलर चलते हैं। उनकी वजह से तो बहुत ही पोल्यूशन हो रहा है और आम लोगों के लिए बीमारी का घर बन गया है। हमारी सरकार को इस विषय में कोई न कोई नियम बनाना चाहिए ताकि पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके और आम जनता आराम से शहर में आ जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, आज एक दिशा की तरफ नहीं बल्कि अनेक दिशाओं की तरफ काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि शिक्षा और हैल्थ है। आज हरियाणा में मैडिकल कालेज सिर्फ रोहतक में है। आज वहां पर मिडिल क्लास का आदमी जाना ही नहीं चाहता है, वहां पर अगर अमीर आदमी

जाएगा तो उसको अटैण्ड कर लिया जाएगा क्योंकि वे वहां पर होने वाले खर्चों को वहन कर सकते हैं। गरीब आदमी वहां पर इसलिए जाएगा क्योंकि उसकी मजबूरी है और वह कहीं और जा नहीं सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर सुधार किया जाए ताकि वह एक अच्छा मैडिकल कालेज बन सके। उपाध्यक्ष महोदय, हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं। हम सोचते हैं कि वहां पर जाकर हमारे बच्चे अच्छे गुण और ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारे बच्चे वहां पर जाकर भटक जाते हैं। वे मुख्यधारा से हटकर शरारती तत्वों के सम्पर्क में आ जाते हैं और अपराध का रास्ता अपना लेते हैं वे आतंकवादी बन जाते हैं। इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि वहां के प्रोफेसर्स कैसे हों, वी०सी० और चांसलर कैसे हों। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस विषय पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। मेरा इस सरकार में विश्वास है कि जिस दिशा में हमारी सरकार चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि जो हमने कभी स्वप्नों में सोचा था कि हमारा हरियाणा ऐसा होना चाहिए, अब वैसा ही हरियाणा बनेगा। हरियाणा में ऐसा विकास किया जाए ताकि हमारे लोग सुरक्षित हो सकें और हरियाणा के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्रीमती अनिता यादव (साल्हवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो माननीय गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज सुबह माननीय गवर्नर महोदय ने यहां पर आकर अपना जो अभिभाषण पढ़ा उसमें काफी अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है। पिछली सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए हामी भरी थी और 24 घंटे बिजली देने की बात की थी। बिजली की समस्या को लेकर अगर हम किसी आफिस में जाते थे तो वहां पर बड़ा भारी कर्पान मिलता था। पिछली सरकार ने वायदा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे और बिजली के तारों को, खम्भों को बदलेंगे लेकिन पिछली सरकार ने अपना वायदा नहीं निभाया। पिछली सरकारों ने हमें प्रदेश की जनता से धोखा किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इतिहास को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि पिछली सरकारों ने केवल मात्र पत्थर लगाने या ओपनिंग करने के अलावा और कुछ नहीं किया इसलिए आज मैं अपनी सरकार से यह उम्मीद करती हूँ कि ट्यूबवैल्वज के कनेक्टिंग लेने के लिए जितनी भी एप्लीकेटिंग पैंडिंग पड़ी है उनको तुरंत प्रभाव से क्लीयर करके कनेक्टिंग दिए जाएं और प्रदेश में जितनी भी बिजली की तारें गली हुई हैं उनको बदलवाया जाए। जिन मकानों के ऊपर से वायरिंग जा रही है उनको तुरंत प्रभाव से हटाकर प्रदेश की जनता को रिलीफ दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का और पानी का आपस में एक गहरा संबंध है। गर्मियां आने वाली हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम

से सरकार से अनुरोध करती हूं कि सबसे पहले जो बिजली की गली हुई तारें हैं उनको हटाकर दूसरी तारें लगवायी जाएं और बिजली का सुचारु रूप से प्रबन्ध किया जाए। ताकि पानी से जुड़ी हुई लोगों की जो समस्या है उसका निदान हो सके।

दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा है। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी इस बारे में बताया है। जितनी भी प्रदेश में इंडस्ट्रीज हैं और जिनमें हमारे किसान भाईयों की जमीन गयी हुई है, मैं चाहूंगी कि उनमें उन किसान भाईयों के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारी सरकार इस बात के लिए भी प्रयासरत है कि वह बेरोजगार भाईयों को रोजगार दें। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिन किसानों के खेतों में फैक्ट्रीज लगी हुई हैं उनका मुआवजा समय के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए और उनके बच्चों को उन्हीं फैक्ट्रीज में रोजगार भी दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी हमारे आई0टी0आईज0 डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको भी इन फैक्ट्रीज में रोजगार दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार भी विधायिका थी इसलिए मैंने देखा है कि इंडस्ट्रीज में ग्रीन ब्रिगेड के रूप में कुछ लोग गलत किस्म का रोल अदा करते रहे हैं। सौ सौ रुपए का जो लालच बेरोजगारी भत्ते के रूप में पिछली सरकार ने हमारे बेरोजगार भाईयों को दिया था वह उनके साथ एक खिलवाड़ था। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार को, अपने मुख्यमंत्री जी को यह अवगत करवाना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने हमारे बेरोजगार भाईयों को इस

तरह का भत्ता देकर उनके साथ एक मजाक किया था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश में जो भी नयी इंडस्ट्रीज लगे, जो भी नये अदायरे लगे उनमें हमारे बेरोजगार भाईयों को जगह दी जानी चाहिए। पिछली सरकार ने जो अच्छे वायदे और सपने लोगों को दिए थे मैं समझती हूँ कि वह केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गए। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि प्रदेश में एक बहुत बड़ी स्कीम वाटर भौंडस की है और उसमें करोड़ों रूपए का बजट सरकार का लगा हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र साल्हावास में लगभग 13-14 वाटर स्कीम्ज हैं लेकिन एक भी वाटर स्कीम उनमें से चालू नहीं है जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र के सबसे बड़े गांव मातनहेल में आज भी दो रूपए का मटका पानी मोल लेकर पिया जाता है। मैं अपनी सरकार से गुजारि करती हूँ कि गर्मियों के आगामी मौसम को देखते हुए पानी का सही रूप से वितरण हो इसलिए जो वाटर भौंड स्कीम्स हैं उनको चालू कराया जाए। अनाज के निकलने का दौर भुरू हो गया है। मेरे साल्हावास विधान सभा क्षेत्र में कोसली एक छोटी सी मंडी है लेकिन वह.....थी जिसने वह मंडी भी नहीं बनाई। उन्होंने मुझे कभी खुलकर बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि जो मंडियों का बारदाना है और जो अनाज और सरसों की खरीद है वह हमारे यहां के ही किसान भाइयों से की जाए क्योंकि दूसरी जगह के व्यापारी कोसली मंडी में आकर अपनी फसल बेचकर चले जाते हैं। और हमारे यहां के किसान मुंह ताकते रह जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि हमारे यहां के किसान की

फसल का एक-एक दाना और उसके बारदाने का सही प्रयोग किया जाए। जहां तक प्रदेश में ला एंड आर्डर की बात थी उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार के समय में बड़ा भारी गदर मचा हुआ था। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। आज हमारे प्रदेश में हमारे विधायक इतने सभ्य ढंग से लोगों को चुनकर भेजे हैं कि सभी इस बात का खयाल रखते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जो हमारे प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए हैं उन सभी से मैं यह गुजारि करती हूँ कि वे ला एंड आर्डर की ऐसी व्यवस्था कायम करें कि जैसे भगवान राम चन्द्र जी का राज हो गया हो (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)। अध्यक्ष महोदय, मैं यही गुजारि करना चाहती हूँ कि हमारे कांग्रेस के राज में प्रदेश में एक ऐसी कानून व्यवस्था हो, जिसका सभी अनुसरण करें। (विधन)

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, अब आप वाइंड अप करें।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी बोलते हुए केवल दो मिनट का समय ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं अपने चैंबर में आपकी आवाज सुन रहा था। Please tak your seat Smt. Anita Ji, (Interruptions) No I am very sorry. Thank you very much (Interruptions)

श्री रमेश कुमार गुप्ता (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है मैं उसका

स्वागत करता हूँ। जो भी कल्याणकारी योजनाएं इस सरकार द्वारा घोषित की गई हैं वे सभी बहुत बढ़िया हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत सारी बातें सदन के सामने लाई गई हैं। मेरे एक साथी विधायक साहेब ने बताया मैं भ्रूणी उस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि पिछली सरकार द्वारा हाउस टैक्स कई गुना बढ़ा दिया गया। जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनके ऊपर हाउस टैक्स का लगभग 20-30 गुना हाउस टैक्स लगा दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हाउस टैक्स प्रपो नैट रेट में बढ़ाया जाए और जो बढ़ा हुआ टैक्स है उसको कम किया जाए। एक पीले और गुलाबी कार्ड की बहुत ज्यादा समस्या है जो हमारे को इलैक्ट्रॉन में देखने को मिली, इसका भी दोबारा व्यापक सर्वे होना चाहिए और जो जरूरतें लोग हैं उनके लिए ये कार्ड ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए।

Mr. Speaker : Now Mr. Karan Singh Dalal will speak. I know Dalal Ji, you are a good orator. But because of the paucity of time, you will be given only 5 minutes. No more time will be allowed. (noise & Interruptions) Please go ahead, now.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हरियाणा के अन्दर नई सरकार बनी है। हरियाणा के लोगों ने इतना बड़ा बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिया है। इस अभिभाषण के

माध्यम से सरकार ने हरियाणा के लोगों की दुख तकलीफों के बारे में चिन्ता जताई है। महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण में जो बातें कहीं हैं वे बहुत अच्छी बातें हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस बारे में आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर ही नहीं, तमाम हिन्दुस्तान और दुनिया के दूसरे कोनों में बैठे लोग जो हरियाणा में रूचि रखते हैं वे यह जानना चाहते हैं कि हमारी नई सरकार पिछली सरकार के मुखिया ओमप्रकाश चौटाला के भासन के समय, उनके परिवारजनों तथा अधिकारियों द्वारा जो गलत काम हुए हैं, उनके बारे में क्या करने जा रही है? अध्यक्ष महोदय, जिन मर्यादाओं को ओमप्रकाश चौटाला की सरकार ने लांघा है ऐसी मिसालें देना तो क्या दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने मेरे बारे में समय का अभाव कहा है इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सीमित समय के अन्दर ही मेरी बातें रिकार्ड पर आ जाएं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला आजाद हिन्दुस्तान के पहले मुख्यमंत्री थे जिनके खिलाफ किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि उनके सगे भाई द्वारा एक एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई गई थी। उनके भाई प्रताप सिंह ने इस एफ0आई0आर0 में उनके खिलाफ आरोप लगाए थे कि किस तरीके से ओमप्रकाश चौटाला ने जब उनके पिता चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे किस तरीके से हरियाणा प्रदेश का खजाना...कौन-कौन सी जायदादें ओमप्रकाश चौटाला जी ने..... की मारफत बनाई। बाद में ओमप्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि उस एफ0आई0आर0

जो उनके अपने विरुद्ध थी अपनी मर्जी का आई०ओ० को लगाकर उसको वापस ले लिया और उन तमाम मुकदमों को उन्होंने खराब किया और अदालत में यह साबित कर दिया कि यह मुकदमा चलाने के योग्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि न केवल उस मुकदमे की बल्कि पिछले साढ़े पांच साल के भासनकाल के दौरान ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने जो हरियाणा में भ्रष्टाचार के नए आयाम कायम किये हैं उनकी जांच हो। अध्यक्ष महोदय, विवेक विश्वविद्यालय और बड़ी-बड़ी संस्थाएं बड़ी रिसर्च करके देश के योगदान में नई बातों को लाने की कोशिश करती हैं लेकिन श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने भ्रष्टाचार फैलाने के तरीके इजाद करके प्रदेश के लोगों के सामने खड़े कर दिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का 36 बिरादरी का नौजवान जो मेहनत करके पढ़ना चाहता था वह उम्मीद करता था कि विवेक विश्वविद्यालयों में जाकर, कॉलेजों में जाकर पढ़ाई करके अपनी मेहनत व लगन से हरियाणा की नौकरियों को प्राप्त करेंगे लेकिन ओम प्रकाश चौटाला और उनके दोनों बेटे जे०बी०टी० के दाखिलों का मूल्यांकन खुद करते थे। जब जे०बी०टी० कोर्स के लिए दाखिला होता था उसकी लिस्ट ओम प्रकाश चौटाला और उसके दोनों बेटे तैयार करते थे कि किस लड़के को इस कोर्स में दाखिला देना है। एच०पी०एस०सी० की बात का माननीय श्री भामदेव सिंह सुरजेवाला जी ने जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, आज मैंने अखबार पढ़ा कि एच०पी०एस०सी० द्वारा जो एच०सी०एस० के पद भरने के लिए

एग्जाम लिया जाता है उसका सारा कन्ट्रोल, एच0पी0एस0सी0 का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिने इन करता है, सरकार इसको इसी बात की तनख्वाह देती है लेकिन चौटाला साहब ने उसको तो घर बैठा रखा था और एच0पी0एस0सी0 के सेक्रेटरी खुद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिने इन का सारा काम करते थे। वे अपनी गाड़ी में बैठाकर कापियों का मूल्यांकन खुद करवाया करते थे। जो उनकी मर्जी के कैंडीडेट्स थे उनको पास कर दिया जाता था। जो लोग उनको धन देते थे वे उनकी सिलैब इन के लिए सिफारि ा करते थे। मुख्यमंत्री, विधायकों और उनके रि तेदारों को एच0सी0एस0 बनाया जाता था। अध्यक्ष महोदय, सर्विस देने के मामले में पहली दफा हरियाणा के भाडूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के भाईयों के साथ ज्यादाती हुई है, नहीं तो पहले कई वर्षों से ऐसा होता रहा है कि जिसमें हरियाणा के हरिजन क्लास का कोई भाई अच्छे नम्बर पाता था और वह अपनी मैरिट से एस0सी0 कैटेगरी की बजाय जनरल कैटेगरी में चयनित होता था और वह एस0सी0 कैटेगरी का कैंडीडेट नहीं माना जाता था। अध्यक्ष महोदय, चाहे तो रिकार्ड मंगाकर देख लें, ओम प्रका ा चौटाला ने किसी एस0सी0 भाई को मैरिट के आधार पर भी रिजर्व कैटेगरी से अलग नहीं जाने दिया। कितना बड़ा अन्याय उनके साथ किया गया? अध्यक्ष महोदय, आज आपके माध्यम से कैंग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसमें बताया गया है कि वर्ष 1999 तक 12 हजार करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा के ऊपर था जो कि 2004 में 22 हजार करोड़ रुपए हुआ है। ओम प्रका ा चौटाला ने अपने परिवार की

राजनीति को चमकाने के लिए कभी राजस्थान से चुनाव लड़ा और कभी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा। आज इस बात की जांच होनी चाहिए कि हरियाणा में कितना बाजरे का उत्पादन हुआ था और हरियाणा की मंडियों में कितना बाजरा खरीदा गया? ओम प्रकाश चौटाला के लोग राजस्थान से कम दाम पर बाजरा खरीद कर उसी बाजरे को सरकारी रेट पर ज्यादा रेट पर हरियाणा की मंडियों में बेचा करते थे और अरबों खरबों रुपए कमाया करते थे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं सस्ते दामों पर खरीद कर उसी गेहूं को हरियाणा के दाम पर मुनाफा कमा कर ज्यादा रेट पर हरियाणा की मंडियों में बेचा करते थे और वह गेहूं आज भी मंडियों में पड़ा हुआ सड़ रहा है बहुत ज्यादा कर्ज ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के लोगों पर खड़ा करके रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, यहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और आज उन्होंने जवाब भी देना है। आज हरियाणा के नौजवान यह जानना चाहते हैं कि हरियाणा की पिछली सरकार ने नौकरियों के चयन में HPSC ने जो.....की, SSB ने जो....की, यूनिवर्सिटीज, मैडीकल कालेजिज और आटोनोंमस बोर्डिज में उन्होंने जिस तरीके से सिलैक्ट करवाया है हरियाणा की सरकार उनका क्या फैसला लेने जा रही है? जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की सरकार ने PPSC के उन तमाम अधिकारियों को जेल में डालकर उनसे उन तमाम बातों को उगलवाया आज हरियाणा को भी उसी रास्ते पर चलने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह नहीं हुआ तो हरियाणा के नौजवानों को बहुत बड़ी निराशा

होगी। जो बच्चे पढ़ लिखकर इस प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं उनके भरोसे को कायम करने के लिए यह सरकार पिछली सरकार को दण्डित करने की बात केवल मन में न रखे बल्कि दोशियों के खिलाफ एक पान लें ताकि आने वाले समय में उन सब लोगों को एक पाठ और सबक मिले कि कोई भी व्यक्ति नौजवानों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करेगा तो उनका हश्र भी वही होगा। हरियाणा की सरकार को यह बताना चाहिए कि इस बारे में वे क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश के अन्दर जो देशभक्त रहे हैं, वे वीर भाहीद जिन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हम उनका आदर करते हैं, उनके बुत लगने चाहिए, प्रदेश में ऐसे लोगों के बुत लगने चाहिए, या उन स्वतंत्रता सेनानियों के बुत लगने चाहिए जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। चौ० देवीलाल के बुत आज हरियाणा में जगह जगह लगे हुए हैं। इस विधान सभा में यह ब्यौरा आना चाहिए कि तमाम ऐसे बुतों पर किस हैड के तहत पैसा खर्च हुआ? यह हरियाणा की सरकार का और जनता का पैसा लगा है। यह किसी के बाप की बपौती नहीं थी कि जहां मर्जी आई बुत लगा दिए। आज हरियाणा की जनता इस बात को जानना चाहती है कि इन बुतों को लगाने के लिए पता नहीं किस हैड के तहत पैसा आता था, कौन उनके टैण्डर्ज भरता था, और किस आधार पर उन बुतों को लगाया जाता था? जनता केवल इसलिए नहीं जानना चाहती कि ये चौ० देवीलाल के

बुत हैं बल्कि इस लिए जानना चाहती है कि आने वाले समय में हरियाणा की धरती पर कोई ऐसा आदमी दोबारा न पैदा हो जाए तो अपने परिवार की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए मनमाने तरीके से इस हरियाणा को हांकना चाहे। इसी तरीके से भ्रष्टाचार के बारे में भी सरकार को देखना होगा। हमारे फरीदाबाद में 90 हजार बड़ी-2 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मुख्यमंत्री ने अपने चहेतों को वहां डी0टी0ओ0 लगाया। वे डी0टी0ओ0 सरेआम एक गाड़ी से 2 हजार रूपए एकत्रित करके जितना धन उनका बनता था अपने पास रखते थे और उस धन में से मुख्यमंत्री के पास भी भेजते थे, आज उस धन की जांच होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि केवल फरीदाबाद के अन्दर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इस तरीके से सरकार के खजाने को.....गया है। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यमुनानगर में जो थर्मल पावर प्लांट न रहा है उसके टैंडर के साथ भी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने छेड़खानी करने की कोशिश की और प्रदेश के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस बारे में मैं आदरणीय जिंदल साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्लांट की फाईल मंगवाएं और देखें कि किस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला

जी ने उस फाईल के साथ छेड़खानी की और सरकार के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में जो भी मरीज बीमारी को चैक करवाने के लिए जाता था उससे पांच रूपए पर्ची के और 100 रूपए भर्ती होने पर बैड के चार्जिज लगा दिए थे। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस गलत आदेश को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं वाईड अप कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि तेजेन्द्र पाल मान जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अकेले उन राजनेताओं को सजा देना काफी नहीं होगा जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया बल्कि जो अधिकारी उनके साथ भ्रष्टाचार में शामिल थे, चाहे वे किसी भी जाति के हों अथवा किसी गुट से संबंध रखते हों जिन्होंने पिछले भासन में मर्यादाओं को लांघकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में है।

Mr. Speaker : Please wind up Mr. Dalal. No doubt, you are talking excellent. But I have no accommodate everyday.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Speaker Sir, I have to make a submission. Mr. Dalal was rightly saying केवल एक टैण्डर की बात नहीं है जितने भी

बड़े-बड़े टैण्डर थे जिनमें करोड़ों रूपए की बात होती थी वे सिंगल टैण्डर अलॉट हुए हैं। अधिकारी हाथ जोड़ देते थे हम नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उनसे करवाया जाता था। पिछली सरकार हर कदम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुलाना जी ने भी कहा कि पिछली सरकार के मुखिया ने हर कदम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। भाराब के ठेकों की नीलाम में भी पिछली सरकार द्वारा बहुत अधिक बेईमानी की गई। ट्रिब्यून में एक बहुत अच्छा आर्टिकल इस बारे में लिखा गया था और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की रूलिंग उसमें दी गई थी जिसमें यह जिक्र किया गया था कि जिस तरीके से ठेकों की बोली छोड़ी गई है वह गलत है लेकिन चौटाला साहब ने उसकी परवाह नहीं की। पानीपत थर्मल प्लांट जहां पर अरबों रूपए का कोयला खरीदा जाता है उस बारे में भी इंगलि । ट्रिब्यून के फ्रंट पेज पर खबर छपी थी कि घटिया किस्म का कोयला खरीदा गया है और उस थर्मल प्लांट को इससे नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि ओम प्रका । चौटाला जी और उनके तमाम अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यदि सरकार को सबूत चाहिए तो तमाम सबूत मेरे पास हैं। अंत में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा (मुण्डाल खुर्द) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जो अभिभाषण आज सुबह राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ सरकार ने मात्र एक महीने से कम समय में जो अपनी इच्छा जाहिर की है, उसका स्वागत करता हूँ। यह स्वागत न केवल मैं करता हूँ बल्कि सभी प्रदेशवासी करते हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को सभी साथियों ने बोलते हुए बिल्कुल छोड़ दिया। जब कभी कोई एथलीट या ओलम्पिक गेम्ज होते हैं तो हम बात करते हैं कि इतनी कम आबादी का कोई देश है जिसके पास कई मैडल्ज हैं लेकिन हिन्दुस्तान की कितनी अधिक आबादी है लेकिन फिर भी हमारे पास कोई मैडल नहीं। यहां पर न किसी के पास गोल्ड मैडल है, न सिल्वर मैडल है और न ब्राउन्ज मैडल है। इन मैडलों के बारे में हम उस वक्त बात करते हैं जब कोई खेल कम्पीटीशन होता है। जब कोई काम करने का समय आता है तो हम सब उसको नजर अंदाज कर देते हैं। इस बारे में मेरा कहना है कि उन स्टेडियमों को आइडेंटिफाई करें कि कहां कहां पर हम स्टेडियम बना सकते हैं? वे स्टेडियम इन्टरनेशनल लेवल के हों। ऐसे स्टेडियमों की हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए ताकि आने वाले 10 सालों में नतीजे आ सकें। केवल ओलम्पिक गेम्ज के लिए बिल्डिंगें बनाने से कोई खिलाड़ी नहीं बन जाएगा और न कोई एथलीट बन जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए आज से प्रावधान रखा जाए। दूसरी

बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम स्पोर्ट्स और हैल्थ को एक साथ इकट्ठा कर लें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि हैल्थ और स्पोर्ट्स की पालिसी सही हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हैल्थ में हमारी पालिसी ढिलमुल रहती है। स्पीकर साहब, अब तक जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं हैं। मेरे से पहले जितने भी वक्ता बोले उन्होंने उन्हीं बातों का जिक्र किया जो बातें हम चुनाव से पहले लोगों के बीच कहा करते थे। यहां पर आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये चीजें भी हमें बर्दा त करनी पड़ेगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में थोड़ा लीक से हटकर काम करें। कई बातें ऐसी हैं कि जब हम पब्लिक के सामने जाते हैं तो हम जवाब नहीं दे सकते। उस वक्त हमें यही कहना पड़ता है कि कानून ही ऐसा है कि ये बातें ऐसे ही चलेंगी। अभी कुछ समय पहले मेरे एक लायक दोस्त ने कहा था कि सिर्फ एम0एल0आर0 के 100/- रूपए लगते हैं। स्पीकर साहब, एम0एल0आर0 बनती है लेकिन कितने में बनती है...यह आपको भी पता है, मुख्यमंत्री महोदय को भी पता है कि और दूसरे मैम्बरान को भी पता है। अगर पिछले 5 सालों की तरह अब भी वैसे ही बनेगी तो लोग हमें कहेंगे कि आप लोग तो पहले भुक्ते हुए थे और भुक्तभोगी थे, उसके बाद भी ऐसा कैसे हो रहा है? अब मैं इलैक्ट्रिसिटी के बारे में कहना चाहूंगा, जब सारे हरियाणा को इलैक्ट्रिफाई किया गया था तो उस समय हमारी आबादी बहुत थोड़ी थी। अब प्रत्येक गांव चारों तरफ बढ़ चुका है। हर भाहर भी बढ़ चुका है। जो गरीब

लोग हैं उनके मकानों के ऊपर से बिजली के तार गए हुए हैं। किसी गांव में भी चले जाएं प्रत्येक गांव में यह समस्या है और जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि इसके लिए ऊपर से बात करनी होगी क्योंकि हमारे पास ग्रान्ट नहीं है इसलिए इसको हम अलाऊ नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, समय के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। उन गरीबों का क्या दोष है जो सुबह अपनी छत पर न जा सकते हों और सर्दी के मौसम में धूप भी न सेंक सकते हों। मैं कई बातें कहना चाहता हूँ। अभी मान साहब ने पीले और गुलाबी कार्ड के बारे में कहा। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि उनके बारे में ध्यान दें और उनको फिर से रिव्यू करवाएं।

अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के बारे में जितना कम्पनसे इन सरकार ने मंजूर किया है वह मैं पेपर में पढ़ता हूँ, वह बहुत ही थोड़ा है। यह तो सिर्फ बीज का पैसा ही है इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि पहले तो वहां पर हम गिड़गिड़ाकर अधिकारियों की मार खाते हैं कि गिरदावरी कितनी हुई। अगर 80 परसेंट लौस है तो 40 परसेंट लौस दिखाएंगे। इस प्रकार से 40 परसेंट लौस तो वहीं रह गया। यहां आकर हमारे रूल्ज ऐसे हैं कि 1000, 1200, 1250 या 1500 रूपए का कम्पनसे इन देते हैं। मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि जहां पर ओलों से लोगों की फसलों का नुकसान हुआ है वहां पर हमें मैकसिमम कम्पनसे इन को देना चाहिए क्योंकि उनके पास

कमाई का और कोई चारा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम कुछ फसल खरीद करते हैं और उनका भाव भी तय करते हैं लेकिन उन फसलों को खरीदने वाली कोई एजेंसी नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सरकारी एजेंसी सरसों को भी खरीदे ताकि जमींदारों को अपना पैसा मिल सके। समय कम होने के कारण मैं और बात नहीं कर पा रहा इसलिए अन्त में मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, जितने हमारे साथी हैं खासतौर पर दक्षिण हरियाणा के साथियों ने पानी की समस्या के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पहली बार साऊथ हरियाणा के किसी व्यक्ति को यह काम दिया है। मैं अपने साथियों को आवासन देना चाहूंगा कि इस बारे में जो सबसे पहला मुद्दा है वह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आफ वाटर है। मैं इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पीने के पानी की समस्या है। वहां पर एक मसानी बैराज बना हुआ था उसको भरने की बात भी की जाएगी और उसके रिचार्जिंग की बात भी की जाएगी। इसी प्रकार से हमीदपुर जो बांध है उसके बारे में भी हम कोर्नर करेंगे कि वहां पर पानी लाया जाये।

14.00 बजे

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पानी पीछे से आ रहा है उससे रि-चार्जिंग भी करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आफ वाटर के लिए हमें एक और कैरियर वाटर चैनल भी बनाना पड़ेगा। हमारा जो दक्षिणी हरियाणा का पानी है उसके लिए सरकार एक स्कीम बना रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि नरवाना ब्रान्च के साथ ही साथ एक और पैरलल चैनल बनाई जाए जिससे कि साउथ हरियाणा में पानी जा सके। इसके लिए बाकायदा हम एक अच्छी स्कीम बना रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो यमुना बेसिन है वहां वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने पानी के लिए काफी सफर किया है और जो स्कीम बनाई जा रही है उसमें न केवल दक्षिणी हरियाणा बल्कि कैथल के एरिया को भी फायदा होगा और जीन्द के इलाके को भी उसका फायदा होगा। केवल साउथ हरियाणा ही नहीं इससे काफी और जिलों को फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय श्री सुरजेवाला जी ने भी कुछ मुद्दे उठाए थे। एक तो उन्होंने कैपटिव पावर का मुद्दा उठाया है। मैं इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे ताकि उससे लाईन लोसिज भी कम हों। हमारी कोशिश है कि लिफ्ट इरिगेशन की जो स्कीम्स हैं वहां पर कैपटिव पावर प्लांट लगाए जाएं और छोटे पावर प्लांट्स बनाए जाएं। 25-25 मैगावाट या 100-100 मैगावाट के पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। इन पर इंस्टॉलेशन चार्जिज तो कम होंगे ही इसके

साथ ही पावर लॉसिज भी कम होंगे। हम डिपार्टमेंट पर डिपेंड ऑन न करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ माननीय श्री सुरजेवाला जी ने बीबीपुर लेक के बारे में बात कही है। मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि यहां पहले बहुत वाटर स्टोरेज हुआ करता था। इस बात को लेकर यहां पर किसानों ने काफी विरोध किया था हम पूरी तरह से इसको एग्जामिन करेंगे और हम कोर्ट में लड़ेंगे कि उससे लोगों को फायदा हो सकें। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कन्टैमिनेटिड वाटर के बारे में खासतौर से कहा गया है। फरीदाबाद का जो हमारा एरिया है वहां पर पोल्यूटिड वाटर जा रहा है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने पहले भी इस बारे में बाकायदा दिल्ली गवर्नमेंट को as a matter of protest का एक लैटर भी भेजा था कि वे इतना गन्दा पानी वहां पर भेज रहे हैं वह ठीक नहीं। हमने उनको यह भी लिखा है कि वे वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाएं। आगरा कैनल और गुड़गांव कैनल की वाटर क्वालिटी बहुत ही खराब आ रही है। उसमें सुधार के बारे में हम दोबारा कोर्ट में लड़ेंगे और मामले को बाकायदा यू0पी0 के साथ टेकअप करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर आगरा कैनल को टेकओवर करने की बात आई। यह दो स्टेट्स के बीच का मामला है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री और स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट में लड़ेंगे कि इसका चार्ज हमारे हाथ में आ जाए। दूसरे एस0वाई0एल0 के अरली कम्पीटीशन के बारे में मुख्यमंत्री महोदय अपने जवाब में बता देंगे। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बारे में हमारे साथ हरियाणा के जितने

भी लोग हैं वे यह चाहते हैं कि एस0वाई0एल0 का पानी हमें जल्दी मिले हम लोगों ने इसके लिए काफी सफर भी किया है। इसको बनवाने के बारे में केस सुप्रीम कोर्ट में है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमें जल्दी ही पानी मिलेगा लेकिन पिछले दिनों पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी कि हम बातचीत से मसले को हल करेंगे यह एक अच्छी बात है। मैं यह कहना चाहूंगा कि 1981 में इन्दिरा जी के द्वारा जो एग्रीमेंट हुआ है उसको उन्होंने रि-अपील कर दिया। उनका पहला कदम यह होना चाहिए कि वे उसकी रिस्टोर करें। हमारा जो पहला एग्रीमेंट था उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए उसके बाद दोबारा से बातचीत भी बात करें। जो एग्रीमेंट पहले हुआ था वह भी तो बातचीत के बाद ही हुआ होगा। जब बातचीत के लिए माहौल बनेगा तो बात हो सकती है लेकिन उसके लिए पंजाब जो कि हमारा बड़ा भाई है, को पहल करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, हमें पूर्ण यकीन है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरा न्याय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना था, धन्यवाद।

डा. शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव पर सहमति के उपरान्त मैं वर्तमान कांग्रेस सरकार को बधाई भी देना चाहूंगा क्योंकि यह सरकार हरियाणा प्रदेश में यह संदेश देने में सफल हुई है कि प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आगे आएगा। इससे प्रदेश के लोगों को आशा की एक किरण दिखाई दी है। अध्यक्ष महोदय, यदि हम स्वस्थ, शिक्षित

और समृद्ध हरियाणा की कल्पना करते हैं तो हमें कुछ बेसिक इशूज ऐड्रेस करने पड़ेंगे। मैं केवल चार प्वाइंट्स बताऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में थोड़ा ध्यान दें। जो बेसिक इशूज हैं वे यह हैं कि हर घर में स्वच्छ पानी होना चाहिए। हर गृहणी जब अपने वाटर बॉण्ड डिस्सिजिज दूर हो सकती है, हर घर में स्वच्छ लैट्रिन होनी आवश्यक है। शौचालयों की समस्या के बारे में हमारी बहनों ने भी जिक्र किया है और बताया है कि यह समस्या कितनी गम्भीर है, दूसरे वक्ताओं ने भी इस बारे में बात की है। इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए इसका निदान होना चाहिए। मेरा तीसरा प्वाइंट यह है कि हर बच्चे को स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए और कम से कम बारहवीं क्लास तक शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। वह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार दिला सके। शिक्षित होकर चाहे कोई नर्स बने, चाहे कोई लैब टैक्नीशियन बने, चाहे कोई मोटर या स्कूटर मैकेनिक बने और चाहे कोई पेंटर बने मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी शिक्षा जिससे बच्चों को रोजगार मिल सके हर बच्चे को मिलनी चाहिए। मेरा चौथा प्वाइंट यह है कि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। हरियाणा में हर वर्ग को और हर जाति को उसका हक मिले। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज जिसके पास कुछ है तो उसको और मिलेगा और जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको भी कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, अगर ऐसा होगा तो ही हम कर सकेंगे कि सोसायटी में प्रोग्रेस हो रही है। मेरे से पहले

बोलते हुए यादव साहब ने भी कहा है और मैं भी भिवानी के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। स्पीकर सर, भिवानी में मैडीकल कॉलेज का पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है और वहां पर मैडीकल कॉलेज खोलने पर सरकार के उपर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा। इसलिए सरकार का इस बारे में विचार करना चाहिए। स्पीकर सर, भिवानी अस्पताल की तरफ जाते वक्ता रास्ते में एक रेलवे फाटक आता है और मुझे नहीं लगता कि वह 24 घंटे में से 12 घंटे भी खुलता होगा। वहां पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फाटक बंद होने की वजह से मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता है और वह फाक पर ही दम तोड़ देता है। अगर कोई औरत प्रैगनैट हो और उसकी डिलीवर का समय नजदीक आ जाता है तो कई बार उसकी डिलीवरी भी फाटक बंद होने की वजह से वहीं पर हो जाती है। ऐसी घटनाएं वहां पर कई बार हो चुकी हैं। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस फाटक पर एक ओवरब्रिज बनवाने का कष्ट करें ताकि वहां पर लोगों को सुविधा प्रदान हो सके। स्पीकर सर, भिवानी में एक व्यापारी लड़कियों का स्कूल बनाने के लिए तैयार है। अगर वहां पर सरकार की तरफ से जमीन मिल जाएगी तो वहां पर लड़कियों का भी स्कूल बन जाएगा। स्पीकर सर, मेरे से पहले बोलते हुए जैसा कि नरेश भाई ने कहा है और लोगों की भी मांग है कि वहां पर एक मैडीकल कॉलेज बनाया जाए। इस पर सरकार गौर करने का कष्ट करे। स्पीकर सर, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी आखिरी बात कहना चाहूंगा क्योंकि आप बार-बार कह रहे

हैं कि समय का ध्यान रखा जाए। मैं बाकी का समय अगली दफा ले लूंगा। इसके अलावा स्पीकर सर, किसी भाई ने प्राईवेट डाक्टर्ज के बारे में टिप्पणी की थी लेकिन मैं उनकी इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूँ। स्पीकर सर, उस भाई को उस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर देना चाहिए। स्पीकर सर, प्राईवेट स्कूलों और प्राईवेट डाक्टर्ज के बिना आज हरियाणा का गुजारा नहीं हो सकता है इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

श्री सुखबीर सिंह (रोहट) : स्पीकर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ध्यान रखा। स्पीकर सर, सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और उस पर बहुत से सदस्य मेरे से पहले बोले हैं। सभी ने चौटाला साहब के वक्त में उनके द्वारा हुए भ्रष्टाचार के बारे में बात की है। मेरा इस विषय में यह कहना है कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए और अगर वे बेकसूरवार हों तो सबको उस बारे में पता चलना चाहिए। जब तक कसूरवार को सजा नहीं मिलेगी तब तक उसको शिक्षा नहीं मिल सकती। अभी सदन में कई साथियों ने दक्षिणी हरियाणा की बात की है कि वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सोनीपत इलाके में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। वहां नहरों में 42-42 दिनों बाद पानी आता है। (विध्न) गवर्नमेंट कॉलेज होना अलग बात है और इंजीनियरिंग कॉलेज अलग बात है। स्पीकर सर, खरखौदा में आज तक कोई भी बस स्टैंड नहीं है और वहां पर यात्रियों को बरसात

में भीगना पड़ता है और अगर गर्मी होती है तो उनको गर्मी में वहां पर खड़े रहना पड़ता है। स्पीकर सर, खरखौदा में हजारों यात्री होंगे जो रोज दिल्ली नौकरी करने के लिए जाते हैं। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि सभी सरकारों के वक्त में उन्होंने दिल्ली तक बस चलाने के लिए एप्लीकेशन दी है लेकिन आज तक वहां से दिल्ली के लिए एक भी बस नहीं लगी है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल ही इन्होंने सोनीपत में फोन किया और उनको कहा है कि वहां पर बस लगा कर इन्हें दो-तीन दिनों में रिपोर्ट करें। इस तरह से अगर सरकार काम करेगी तो मेरे हिसाब से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सरकार कम से कम बीस साल चलेगी किसी और सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतने ईमानदार आदमी आ जाएंगे तो औरों की क्या जरूरत है? अध्यक्ष महोदय, सभी ने पीले कार्ड के बारे में भी यहां पर चर्चा की। चौटाला सरकार ने गरीबों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया बल्कि उन्होंने तो पूरी तरह से गरीबों का शोषण किया है। अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी की जो सेवा करता है वह क्लीयर कट बात है कि उसका अहसान गरीब आदमी डबल सेवा करके उतारता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि गरीबों को प्लॉट जरूर मिलने चाहिए। सरकार की तरफ से हर जगह जमीन एक्वायर की जानी चाहिए और गांव में जिनके पास जमीन नहीं है उनको स्पेशल प्लॉट्स दिए जाने चाहिए। अफसर विधायकों के पास आएँ और विधायक अफसरों के साथ जाएंगे और जाकर खुद जांच करवाएंगे। असलियत में जो गरीब हैं उनके

पीले कार्ड बनने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ए0बी0सी0 कम्पनी का अपने राज चला करता था। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि एम0एल0एज0 को अपने अपने हलकों में काम करवाने के लिए लोकल डिवल्पमेंट फंड जरूर दिया जाना चाहिए। एम0पी0 को भी दो करोड़ रुपया मिलता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस बारे में उदारता दिखानी चाहिए और सबको दिखाना चाहिए कि हमने यह शुरुआत की है। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि 90 के 90 एम0एल0एज0 चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि देवीलाल जी ने पेंशन के सौ रुपए किए थे। गांवों में चर्चा चलती रहती है कि यह तो देवीलाल पेंशन है। हमने लोगों को बहुत समझा लिया कि आज तक किसी संस्था को देवीलाल परिवार ने अपनी जेब से अगर दान दिया हो तो बताएं लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सौ रुपए पेंशन और बढ़ा दी जाए ताकि पेंशन के साथ उनका नाम हट जाए। अगर 1991 में कांग्रेस सरकार 200 रुपए कर देती तो देवीलाल जी का पेंशन से नाम हट जाता तो बाद में चौधरी बंसीलाल के समय में 50 रुपए भी बढ़ा दिए जाते तो भी उनका नाम इस योजना से हट सकता था। अध्यक्ष महोदय, मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि अगर एक लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दो तो पहली लकीर अपने आप छोटी हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह काम भी होना चाहिए। इसके अलावा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने जा रही है

ओचन्दी बोर्डर पर जो औद्योगिक एरिया बसने लग रहा है। उसका परिजोन किया जाना चाहिए। इसके अलावा खरखौदा में जो लड़कियों का कॉलेज है उसको सरकार अपने अधीन लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक प्वायंट को क्लियर करना चाहती हूँ। यह बड़ी भ्रान्ति है बड़े दुख की बात है कि लाखों लोगों को जिनको चुनकर भेजा है उनके मन में भी यही बात है। अध्यक्ष महोदय, पेंशन का जहां तक सवाल है, सभी माननीय सदस्यों को यह ध्यान होना चाहिए कि यह बुढ़ापा पेंशन जब राजाओं महाराजाओं के प्रिवीपर्स खत्म हुए थे तो उसके बाद फ्रीडम फाइटरज को पेंशन दी जानी शुरू की गयी थी और जो धन बचा था उससे असहाय और गरीबों को पेंशन देने की स्कीम श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू की थी। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि पहले यह 60/- रूपए थी। जब मैं 1989 में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी तो सुरजेवाला जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह सिफारिश की थी कि यह 60 रूपए की राशि कम है इसलिए इसको सौ रूपए किया जाना चाहिए। 1987 में देवीलाल जी की सरकार आयी तो उनको 60 रूपए की जगह 100 रूपए अनाउंस करने का मौका मिल गया। मैं यह नहीं कहती कि उन्होंने घर से की या क्या की लेकिन यह

कहना कि यह पेंशन देवीलाल जी ने दी, यह कहना बिल्कुल गलत है। पेंशन देनी तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू की थी।

चौ० अर्जन सिंह (छछरौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। वैसे तो सारी बातें हमारे सीनियर साथियों ने रख दी हैं यदि मैं उनको दोबारा दोहराना चाहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे साथियों ने जो बातें कहीं हैं मैं उन सभी बातों से सहमत हूँ। मेरा आपसे और मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध है कि मेरा हलका जहां से मैं चुनकर आया हूँ वह तीन राज्यों से उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश से लगता है। मैं चाहता हूँ कि हमारी स्टेट की बाउंड्री ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बाहर से आने वाले को ऐसा लगे कि बहुत ही अच्छा राज्य है। जब चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसा ही उदाहरण बना था। सुरजेवाला जी ने एक समस्या रखी थी कि लड़के और लड़कियों की ग्रोथ रेट में फर्क है। पहले हम उधर से उत्तरप्रदेश से लड़कियां ब्याह कर ले आते थे इससे हरियाणा में जो लड़कियों की कमी थी वह भी पूरी हो जाती थी। मैं चाहता हूँ कि अब भी ऐसी बाउंड्री बना दी जाए कि बाहर से आने वाले को लगे कि हरियाणा प्रदेश में आ गए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सरकार को माइंस की वजह से, माइंस से निकलने वाली रेत, रोड़ी, बजरी की वजह से सबसे ज्यादा आमदनी मेरे हलके से है लेकिन वहां शिक्षा का व सड़कों का बहुत बुरा हाल है

और वहां पर अनपढ़ता भी बहुत अधिक है, अनपढ़ता इसलिए है क्योंकि वहां कॉलेज नहीं है। लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वे अपने बच्चों को दूर पढ़ने भेज सकें। वहां बसों की भी बहुत कमी है इसलिए वहां पर बसें भी उपलब्ध कराई जाएं। मैं तो इंतजार कर रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी और वह ही दोबारा यह उदाहरण पेश करेगी। इसके अलावा यह जो राशन कार्ड का मामला है कैटेगरी बन रही है इसमें एक समस्या और बढ़ रही है कि कैटेगरी तो बन दी लेकिन वह कैटेगरी किस ढंग से बना दी कि एक बेचारा लोन लेकर मकान बना रहा है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाता जब तक किश्त ही न उतरे तो मकान उस गरीब का कैसे हुआ? लेकिन पीले या गरीब राशन कार्ड बनाते समय कह दिया जाता है कि तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बन सकता क्योंकि तुम्हारा पक्का मकान है और उसमें पंखा आदि लगा हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि जब उसके मकान की लोन की किश्तें उतर जाएंगी तभी वह उसका मकान होगा। एक मेरे हलके में जमींदारी की बहुत प्रथा है कोई आदमी कर्जा उतारने की कैपेसिटी नहीं रखता लेकिन फिर भी वह मजदूरी में कर्जा ले रहा है। वह दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा है लेकिन कर्ज नहीं उतार पा रहा है उसको जेल में मत भेजो वे बेईमान नहीं हैं लेकिन इस हालत में नहीं पहुंचे कि कर्ज उतार सकें तो मेरी आपसे अपील है कि उनकी कर्जा चुकाने की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। (शोर एवं विघ्न)

सुश्री शारदा राठौर (बल्लभगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के द्वारा सरकार की नीतियां और कार्यक्रम सामने आए, जो निश्चित ही प्रशंसनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि जो बातें कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले अपने मैनीफैस्टों में कही थी, जो घोषणाएं की थी घोषणा पत्र में उन्हीं घोषणाओं को जारी करने के लिए आज सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की एक झलक सामने आई। यह बहुत ही अच्छी बात है कि जिस मुद्दे पर पिछली सरकार गई और जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला वह था भ्रष्टाचार का मुद्दा और भय और आतंक का मुद्दा। मुख्यमंत्री जी ने उसी मुद्दे को प्राथमिकता दी है कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे व ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। इस अभिभाषण में भी कहा गया है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा जो निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे और भय को खत्म करने के लिए कार्य करेंगे और लॉ एण्ड आर्डर को मेनटेन रखने के लिए कार्य करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को जो इन घोषणाओं को लागू करने में सहयोग करेंगे उनको जिला स्तर पर सम्मानित किया जाए और ऐसे अधिकारियों को प्रमोशन भी दिया जाए। ऐसे कार्यक्रम समय-समय पर और निश्चित अवधि पर चलते रहने चाहिए ताकि इस योजना को बल मिल सके। हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले पांच साल में जितनी हत्याएं और आत्म हत्याएं हुई हैं, लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, जितनी अपहरण की घटनाएं हुई हैं। उतनी इससे

पहले कभी देखने को नहीं मिली। हम पूरे पांच साल तक इन वारदातों के खिलाफ धरने, प्रदर्शन जलूस निकालते रहे हैं। पुलिस का इतना आतंक और भय था कि वहां पर धरने और प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमे दर्ज कराए गए। मुझ समेत बहुत सी महिलाओं पर मुकदमे दर्ज हुए जबकि हम शान्ति से प्रदर्शन करते थे परन्तु हम पर फिर भी मुकदमे दर्ज किए गए। बल्लभगढ़ की तिरका कालोनी में भीड़ पर लाठी चार्ज किया गया और गोलियां चलवाई गईं। मैं महिलाओं के हित के लिए महिला कमीशन गई, राष्ट्रीय महिला आयोग गई और वहां से आयोग के प्रतिनिधि ने आकर वहां पर दौरा किया और प्रशासन के खिलाफ गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी। उसके बावजूद भी 16 आदमियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए थे वे सरकार ने वापस नहीं लिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो बेकसूर लोग हैं और जिनके खिलाफ गलत मुकदमे बनाए गए हैं वे सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। जहां तक कृषि का सवाल है, कृषि के बारे में बहुत से विधायकों ने बहुत सी बातें कहीं हैं। मैं सरकार की कृषि नीति का पूरा समर्थन करती हूं। सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लायमेंट की है। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं तो जो हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा हमारे नौजवानों और महिलाओं का होता है, वह बेरोजगारी का होता है। यह सरकार रोजगार दिलाने के लिए कटिबद्ध है व प्रयासरत है। यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं बताना चाहूंगी कि उद्योग का इम्प्लॉयमेंट देने में एक अहम रोल है क्योंकि सभी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती।

फरीदाबाद जो कभी एशिया में उद्योग के मामले में नम्बर वन पर था। फरीदाबाद से आज उद्योग पलायन कर रहे हैं। 1996 के बाद की सरकारों की वजह से ऐसा हुआ और वहां से उद्योग बन्द होते चले गए। व्यक्तिगत रूप से हम जब इण्डस्ट्रलिस्ट्स से बात करते हैं कि क्या वजह है कि आप फरीदाबाद से अपने उद्योगों को पलायन कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि जो व्यापारी एक रूपया कमाता है तो उसका 75 प्रतिशत तो मुख्यमंत्री और उसके बेटे हम से....ले जाते हैं और 25 प्रतिशत अधिकारी....ले जाते हैं इसलिए हम अपने उद्योगों को दूसरे प्रदेशों में ले जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि फरीदाबाद में जो सिक यूनिट्स हैं जो बन्द हो गई हैं, जो बाहर चली गई हैं उसके लिए कोई इण्डस्ट्रियल डिवैल्पमेंट कमीशन बनाया जाए जो हमारे उद्योगों को बढ़ावा दे। इससे उद्योगों को स्थापित करने में काफी सहायता मिलेगी। महिलाओं और युवाओं की भी मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि महिलाओं और युवाओं का आपस में साथ है। मां के ही बेटे युवा होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं महिलाओं की जो समस्याएं हैं मुझ से पहले भी उठाई गई हैं क्योंकि आज हर गांव में 500-700 के करीब लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सरकार इस बारे में योजना जरूर बनाये और उसको सख्ती से लागू करे। महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए उनको कर्जा देने के लिए कानून को लचीला बनाया जाए और उनकी शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध किया जाए। हमारे छात्र कल के भविष्य हैं। अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया

तो हम अपने सुखद और खुशहाल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए छक्कड़ रूँ को ज्यादा सख्त किया जाए। आर्थिक रूप से सशक्तकरण की बात भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने सामने रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि महिलाओं को नौकरियों में हिस्सा दिया जाए। सरकार कोई ऐसा कानून लाए जिससे हमारी महिलाओं को नौकरियों में हिस्सा दिया जा सके। महिलाओं के लिए कर्जे के लिए भी आसान किशतों की और कम ब्याज की योजनाएं बनाई जाएं जिससे महिलाएं लाभान्वित हो सकें। मेरे से पहले सुमिता जी ने कहा था कि महिलाओं के लिए वन विंडो सिस्टम होना चाहिए, यह बहुत सही बात है, महिलाओं में जागृति आनी चाहिए, उन्हें नहीं पता कि सरकार उनके लिए क्या-क्या योजनाएं लाती है। महिलाओं और युवाओं के लिए जो भी योजना लाई जाए उनके प्रसार और प्रचार में कोई कमी न छोड़ी जाए। इसके लिए जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर प्रचार और प्रसार में कोई कमी न छोड़ी जाए। वृद्धावस्था पेंशन की बात यहां आई है। आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यह पेंशन स्कीम लागू की थी, यह सही बात है। आज कई जगहों पर हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो पेंशन के लाभ से वंचित हैं। इस पेंशन को बांटने के लिए भी पक्षपात किया जाता है। जो लोग इसके लिए इलीजिबल नहीं हैं, जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है वे इसका लाभ उठा रहे हैं और घर में कई कई लोग इस पेंशन को ले रहे हैं और जिन्हें वास्तव में मिलनी चाहिए उन्हें नहीं मिल रही है।

हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि बुजुर्गों के पास चश्मा नहीं है वे चश्में पर डोरी बांधकर गुजारा कर रहे हैं। उनके चश्मे का एक लेंस क्रेक है वे उसी से ही गुजारा चला रहे हैं। बुजुर्गों की स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं बताई गई हैं वे प्रशंसनीय हैं। बुजुर्गों के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी उनकी जरूरतें हैं जैसे किसी को कान की मशीन चाहिए, किसी को चश्मा चाहिए, ऐसी जो भी सुविधाएं हैं वे सभी सीनियर सिटीजन्स को दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप वाइंड अप करें।

सुश्री शारदा राठौर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात और कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। एजुकेशन के बारे में अभी महेन्द्र प्रताप जी ने बताया कि फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कैम्पस या ब्रांच बनाई जाए क्योंकि फरीदाबाद काफी रवैन्सू देने वाला जिला है और फरीदाबाद हरियाणा का कमाऊ पूत है। हमें एजुकेशन से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। बल्लभगढ़ विधान सभा क्षेत्र के मोटूका गांव में 89 एकड़ जमीन पिछली सरकार ने एक्वायर की थी ताकि वहां जेल बनाई जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी उसका उदघाटन नहीं कर पाए, शायद इसमें भी कोई अच्छाई छुपी होगी। उनका इरादा मुझे पता नहीं लेकिन लोग कहते हैं कि उन्हें किसी इंडस्ट्रलिस्ट ने कोई और योजना बता दी थी तो उन्होंने अपना इरादा उसी वक्त कैंसिल कर दिया। इस सरकार में शायद वहां कोई अच्छा काम

उस जमीन पर हो जाए। वह 89 एकड़ जमीन अभी खाली पड़ी है और उस पर कुछ नहीं बना। मैं चाहूंगी कि वहां पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट सरकार लेकर आए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगी कि अब आगे गर्मी का मौसम आने वाला है। सरकार द्वारा प्रदेश में बिजली और पानी को प्राथमिकता देनी चाहिए। फरीदाबाद नगर निगम को सम्भालने के लिए पहले कमिश्नर हुआ करता था लेकिन पिछले मुख्यमंत्री महोदय ने यह काम उपायुक्त को दे दिया था जिससे हमारे नगर निगम का काम सफर करता है। मैं चाहूंगी कि वहां पर फिर से कमिश्नर को लगा दिया जाए ताकि फरीदाबाद नगर निगम का काम सुचारू रूप से चल सके। चुंगी को फिर से चालू किया जाए ताकि नगर निगम की इन्कम हो सके। मैं। यह भी कहना चाहूंगी कि जमीन का जो कलैक्टर रेट बढ़ा हुआ है उसको भी कम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया।

Mr. Speaker : Now , the Chief Minister, will give reply.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया और हमारे वरिष्ठ साथी चौधरी शमशेर सिंह जी ने उनका धन्यवाद करने जो प्रस्ताव रखा है इससे पहले कि मैं

उस पर चर्चा करूं मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि आज विश्व जल दिवस है। मैं विश्व जल दिवस के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सभी को मालूम है कि जल ही जीवन है। पानी की समस्या आज हम सबसके सामने बहुत अहम समस्या बनी हुई है। आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यह समस्या और अधिक गहरा सकती है तथा विकराल रूप ले सकती है। अध्यक्ष महोदय, जैसे आज यह आम चर्चा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के लिए होगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि हम सबका यह प्रथम कर्तव्य है कि हम सब जल संरक्षण का हर संभव प्रयास करें ताकि इस संकट से हम बाहर निकल सकें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आना चाहूंगा। चुनावों में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को शासन सौंपा है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी 120 साल पुरानी पार्टी है और लोगों ने बहुत ही आशा और उम्मीदों से कांग्रेस पार्टी का यह शासन सौंपा है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग, कुर्बानियों और स्वतंत्रता संग्राम से लिखा हुआ है। इसमें महात्मा गांधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जी के जो सपने थे वे आज श्रीमती सोनिया गांधी जी के कुशल नेतृत्व में साकार होंगे। मैं यही विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे जो महान नेता रहे हैं। उनके सपनों को साकार करने में किसी प्रकार की कोई कसर हमारी सरकार नहीं

छोड़ेगी। यानि हम अपने महान नेताओं के सपने पूरे करने के पुरजोर प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने हरियाणा के नव निर्माण की आज जो परिकल्पना की है, उन्होंने इसे ब्रोड बेस्ड थ्रस्ट बताया है। हम पूर्ण रूप से नीति की घोषणा तो आने वाले समय में करेंगे। जिन चीजों की चर्चा मेरे साथियों ने की है मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी के सहयोग से समृद्ध, सुदृढ़ता, स्वस्थ, शिक्षित और सुरक्षित समाज का सुन्दर हरियाणा अब बनकर ही रहेगा। मैं कल्पना में विश्वास नहीं रखता। मैं ठोस परिणामों में विश्वास रखता हूँ और जो बातें मैंने कही हैं परिणामों में उनको आंका जाएगा। हरियाणा की जनता ने जिन आशाओं और उम्मीदों से हमें यह जिम्मेवारी दी है इस पर हम खरे उतरेंगे। We are here not to rule but to serve the people of Haryana. त्यागमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी जी के ओजस्वी नेतृत्व और कुशल नेतृत्व में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो जिस जगह भी वे हरियाणा में आईं और इस देश के प्रधानमंत्री जी जहां पर भी विधान सभा चुनावों में आए थे तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे। जब यह बागडोर कांग्रेस पार्टी ने संभाली और थोड़े दिन के शासन के बाद जो हमारा तर्जुबा हुआ, मैं किसी की निंदा करने का आदी नहीं लेकिन जहां पर भी देखा और गहराई से सोचा कि हमारे प्रदेश का बहुत बुरा हाल है। सभी साथियों ने भी इस बारे में चर्चा की और कांग्रेस पार्टी ने पिछली सरकार के कार्यों की एक चार्जशीट भी

राज्यपाल जी को दी थी इस बात की चर्चा चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने भी की कि किस-किस तरह के घोटाले पिछली सरकार के समय में हुए। यह बात किसी से छिपी नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता को इस बारे में मालूम है। अध्यक्ष महोदय, पिछले लोक सभा चुनावों में हरियाणा की जनता ने चौटाला साहब की सरकार को संदेश दिया था लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली और लोक सभा के चुनावों के बाद से लेकर विधान सभा के चुनावों के बीच में उन्होंने जो निर्णय लिए हैं उनसे हरियाणा का बहुत अहित हुआ है। उन्होंने जो फैसले इस दौरान लिए ऐसे फैसले किसी भी प्रजातांत्रिक प्रदेश के इतिहास में देखने को नहीं मिलेंगे। इस दौरान जिन संस्थाओं पर हमारा भविष्य निर्भर है उनके बारे में पिछली सरकार ने क्या-क्या फैसले लिए इस बारे में सबको जानकारी है। किस तरह से समय से पहले ही एच0पी0एस0सी0 के मੈंबरो के इस्तीफे दिलवाकर नए मੈबर रातो-रात बनाए ताकि आने वाले 6 साल तक वे उस पद पर रह सकें और वे अपनी मनमानी कर सें, ये बातें किसी से छिपी नहीं हैं। स्पीकर साहब, पिछली सरकार द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण दिया है उसमें सरकार की एक एक ब्रोड बेस्ड दिशा दर्शायी गई है। हमारी मौजूदा सरकार नई दिशा और नई गति व नव निर्माण हरियाणा में देने के लिए वचनबद्ध है। हरियाणा में हर नागरिक को मान-सम्मान दिया जाएगा और उनकी

भावनाओं की रक्षा की जाएगी। सभी प्रकार की संस्थाओं के गर्व और गरिमा को बहाल किया जाएगा चाहे वह चयन की संस्था है या नौकरियों की संस्था है और चाहे लेजिस्लेचर है। कहने का मतलब यह है कि चाहे पंचायती राज की संस्था है या कोई और संस्था है, सबका मान-सम्मान बहाल किया जाएगा। पंचायती राज के बारे में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने घोषणा की थी उसके बारे में वे जो अमेंडमेंट लेकर आए थे उन्होंने उसे पास भी करवाया था। स्वर्गीय महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज का जो सपना था उसे पूरा करने का राजीव जी ने इस अमेंडमेंट के जरिये प्रयास किया था। पिछली सरकार ने किस प्रकार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों के हितों से खिलवाड़ किया वह सभी को पता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कार्य पंचायतों का था उस कार्य को भी करने के लिए मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते थे। उन्होंने विकास समितियां बना दी। जो पंचायतें लोगों ने चुन करके भेजी थी वे डिफैक्ट कर दी गई। चाहे वे पंचायतें हैं, चाहे पंचायत समितियां हैं और चाहे जिला परिषद है। हमारी सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध भी है कि जो ऐसी सभी संस्थाएं हैं उनकी गरिमा और उनकी क्रेडिबिलिटी कायम की जाए। अब पूरे प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं। लोगों की मन्शा से पंचायतें चुनी जाएंगी और अपने अपने कार्य क्षेत्र में वे संस्थाएं पूर्ण स्वतंत्र होंगी। इसमें किसी प्रकार का कोई दखल सरकार की तरफ से नहीं होगा। मैं पावर पोलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता। मैं राजनीति में हूँ और मेरे लिए राजनीति सेवा का एक माध्यम है।

मुझे विपक्ष में रहते हुए पिछली सरकार का जो तजुर्बा हुआ है उससे तो यही लगता है राजनीति में जो भी आता है वह चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ते वक्त वह यही कहता है कि मैं जनता की सेवा करने में लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछली 2000 के चुनावों में लोग एक नई सरकार इस उम्मीद से यहां पर ले करके आए थे कि वह सरकार प्रदेश का भला करेगी लेकिन सिद्ध यह हुआ कि वे लोग जनसेवा का नाम लेकर सत्ता में आ गए तो फिर वे जनसेवा के बजाय स्वयंसेवा में लग गए। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को यकीन दिलाता हूँ कि इस सरकार में पहले की सरकार की तरह ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं पालिटिक्स ऑफ डिवलपमेंट में यकीन रखता हूँ। मेरे साथियों का भी इसमें यकीन है। विकास की पहली आवश्यकता किसी भी प्रदेश की हो उसके लिए जरूरी है कि वहां पर शांति और सुरक्षा लोगों को मिले। यहां पर जैसा राज्यपाल महोदय ने दर्शाया है और बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो कभी शांति कायम नहीं हो सकती। यह बस तभी संभव होगा जब प्रदेश से भ्रष्टाचार का सफाया हो। यह निश्चित है कि भ्रष्टाचार और गरीबी दोनों सगे भाई-बहन हैं। जहां पर भ्रष्टाचार होगा वहां पर गरीबी का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। सरकार की कोई भी नीति हो और कितना भी पैसा आता हो, वह नीचे तक नहीं पहुंचता। भ्रष्टाचार के बारे में राजीव गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि अगर ऊपर से एक रुपया चलता है तो नीचे तक सिर्फ 10 पैसे पहुंचते हैं। यहां का अगर इतिहास खोल कर

देखें तो कोई यकीन नहीं करेगा कि उस समय किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग हुआ था। हम गलत कामों की समीक्षा करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में और मेरे बहुत सारे माननीय साथियों ने सरकारी ऑफिसर्ज और राजनेताओं की भी बात कही है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि हमारी नीति रिवार्ड और पनिशमेंट की होगी। जो भी अधिकारी अच्छा काम करेंगे और जनहित के काम करेंगे उनको पूरा मान-सम्मान मिलेगा और उन्होंने प्रोत्साहित किया जाएगा लेकिन अगर कोई अधिकारी किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार करेगा या भ्रष्टाचार की बात करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। (इस समय मेजें थपथपाई गई) सजा के जो तरीके बने हुए हैं उनके मुताबिक सजा दी जाएगी। केवल बदली करना कोई सजा नहीं होगी बल्कि दूसरी तरह की सजा भी उसमें होगी। अध्यक्ष महोदय, यहां पर सारे क्षेत्रों की बातें आईं। हमारे साथी रणवीर सिंह जी ने कहा स्पोर्ट्स के मामले में यहां पर कोई चर्चा नहीं हुई। मैं हाउस की जानकारी के लिए यह कहना चाहूंगा कि जल्दी ही हम इसके बारे में पूरी पॉलिसी लाएंगे जिसमें खेलकूद की सारी बातें होंगी। महिला सशक्तिकरण हो या दलित भाईयों के लिए राहत की बात हो, सब के लिए अलग-अलग से कार्यक्रम होंगे क्योंकि अगर प्रदेश को अच्छा साबित करना है तो हमें यह सब करना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि हम एक ही लक्ष्य लेकर

चले हैं कि आने वाले चुनाव तक हरियाणा पूरे देश का नम्बर एक प्रदेश होगा। प्रदेश को नम्बर वन बनाने के लिए हमें प्रदेश का चहुंमुखी विकास करना चाहिए। वह विकास चाहे स्पोर्ट्स का हो या किसी और चीज का हो हम सब करेंगे। चहुंमुखी विकास का रास्ता है जो प्रदेश को आगे ले जा सकता है। विकास की गंगा सारे प्रदेश में बहे इसके लिए हम सब को मिलकर काम करना होगा और हम इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। शायद यही कारण है कि आज से करीब डेढ़ साल पहले गंगा मैया ने मुझे जीवनदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, बाकी का जो जीवन है बगैर किसी कुर्सी के लालच के मैं वह जीवन हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा में लगाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। जहां तक किसान का सवाल है, पिछली सरकार अपने आप को किसानों की हितैषी सरकार कहती थी लेकिन किसानों की जो दुर्दशा उस सरकार ने की थी वह सबको मालूम है। कैसे किसानों के साथ खून की होली उस सरकार के समय में खेली गई थी, हरियाणा के इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मैं खुद और मेरे साथी कण्डेला और गुलकनी गांवों में मौके पर गए थे और किसानों की हालत को देखा है। सरकार के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन हुआ करते हैं, प्रजातन्त्र में सभी लोगों को अपनी मांग रखने का अधिकार है और उसका तरीका भी है लेकिन किस प्रकार से खेतों में खड़े लोगों

को गोलियां से भूना गया लोग उसे भूले नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। अंग्रेजों के राज में तो हमने सुना था कि लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होते थे लेकिन हिन्दुस्तान में हमने केवल हरियाणा में ही सुना है कि जो लोग किसानों के हित की बात उठाते हैं उन पर देशद्रोह के मुकदमे बनाए गए। घासी राम जैसे नेताओं पर सरकार ने कई केसिज बनाए। हमारी सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला किया है कि इस किस्म के जितने भी मुकदमे बनाए गए हैं वे वापिस लिए जाएंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गई) अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने पहले फरवरी के मास में पड़े हेल्स्टॉर्म और अब फिर हेल्स्टॉर्म पड़ने की चर्चा की। इस ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की बात आई और कुछ साथियों ने कहा कि मुआवजे के रूप में जो राशि एनाउंस की गई है वह काफी कम है। फरवरी के महीने में किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कम्पनसेशन अमाउंट हैं वह इनपुट कॉस्ट से रिलेटिड है यानि जितनी लागत है उससे रिलेटिड है। जिन फसलों को नुकसान हुआ है उनमें गेहूँ की भी एक फसल है, चना और दूसरी फसलें भी हैं लेकिन गेहूँ की जो फसल है उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट सबसे ज्यादा है इसलिए हमने फैसला किया है कि फरवरी में सरकार ने एक हजार रूपए पर एकड़ का जो मुआवजा घोषित किया था उसे बढ़ाया जाए। जिस किसान का नुकसान 26 से 50 प्रतिशत तक हुआ है उसके बारे में हमने फैसला लिया है कि हम

उसको मुआवजा एक हजार रूपए प्रति एकड़ की बजाय डेढ़ हजार रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। इसके अलावा और दूसरी फसलें हैं हमने उनके मुआवजे में 25 प्रतिशत का इजाफा किया है। स्पीकर सर, जहां पर 75 प्रतिशत नुकसान हुआ है वहां पर हमने फैसला लिया है कि दो हजार रूपए प्रति एकड़ की बजाय तीन हजार रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। सदन में कृषि के विविधीकरण के बारे में चर्चा हुई है। मैं पिछली सरकार के वक्त में अपोजिशन में बैठता था और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी यहां पर मेरी जगह पर बैठा करते थे और वे बार बार यह कहते थे कि किसानों को फूल पैदा करने चाहिए। यह ठीक है कि फसलों का सर्कल स्ट्रेंग्थनिंग कम हो जाती है। आज किसानों की होल्डिंग कम हो गई है। अगर किसान की आमदनी बढ़ानी है तो हमें फसलों का विविधिकरण करना होगा और कहीं पर फ्रूट्स और कहीं पर सब्जियों को लगाना होगा। लेकिन उससे पहले हम किसानों को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो हमें उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो बात हमने कही है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्पीकर सर, पशुपालन और डेयरी फार्मिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा क्योंकि यही वे दूसरे धन्धे हैं जिनको किसान आसानी से कर सकता है। स्पीकर सर, सदन में मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि दुनिया में गायों और भैंसों की बढ़िया नस्ल को देखने के बारे में एक लेटैस्ट रिसर्च हो गई है। उस रिसर्च में दुनिया भर से गायों और भैंसों को शामिल किया गया था और उस रिसर्च में हरियाणा की गायों और भैंसों को

अव्वल नम्बर का पाया गया है। स्पीकर सर, गांवों में फलों और सब्जियों की स्टोरेज होनी चाहिए। जब तक इस फैसिलिटी को देने के पूरे प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक गांव वालों को फायदा नहीं हो पाएगा। हमारे सदन के एक सदस्य सीता राम जी, जो कि पिछली सरकार के वक्त में भी हमारे साथ सदन में थे, ने बोलते हुए कहा कि यह पानी उत्तरी हरियाणा में जाएगा या नहीं जाएगा। मैं इनको यह कहना चाहूंगा कि हमने न्यायोचित पानी के बंटवारे की बात की है। जिसका जितना हक है उसको उतना हक मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज तक हरियाणा में पानी के बंटवारे में इन्साफ नहीं हुआ है, न्यायोचित बंटवारा नहीं हुआ है। मेरे पास सारा इतिहास है और उस बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। हमारे शमशेर सिंह जी भी मंत्री रहे हैं और दूसरे साथियों को भी ज्ञान है और जिनके जिनके शासन रहे हैं उनको भी यह ज्ञान था। स्पीकर सर, जब से हरियाणा बना है तब से हरियाणा में पानी का बंटवारा न्यायोचित ढंग से नहीं हुआ है। व्यास का, जो पानी है वह 1977 में पहली दफा हरियाणा की भूमि को टच हुआ था, तब चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री थे और तब से ही पानी के बंटवारे में.....का काम शुरू हुआ था। आज वे भगवान को प्यारे हो गए हैं। मैं उनकी सदैव इज्जत करता रहा हूं। वे स्वतन्त्रता सेनानी थी और मेरे पिता जी के साथ थे लेकिन हकीकत हो हकीकत है। मैं आज आप सभी के सहयोग से मुख्यमंत्री हूं। चाहे हरियाणा में कोई भी मुख्यमंत्री हो और जो भी मुख्यमंत्री होता है वह प्रदेश का हैड होता है, वह एक परिवार में

बाप की तरह होता है। मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि अगर एक बाप के चार बेटे हैं और उस बाप के पास चार बेटियां हैं, अगर वह बाप चारों बेटों में एक एक रोटी बांट देगा, चाहे बच्चे भूखे ही रहें, समाज यह कहेगा कि बाप ने बच्चों के साथ इन्साफ किया है लेकिन एक बाप के चार बेटे हैं और उस बाप के पास चार रोटियां हैं, अगर वह बाप तीन रोटियां एक बेटे को दे दे और एक रोटी तीन बेटों में बांट दे तो कौन सा समाज यह कहेगा कि यह न्याय किया है लेकिन ऐसा अन्याय हरियाणा में होता रहा है। हमारे सिंचाई मंत्री ने भी इस बात की चर्चा की है और यही बात सोचकर कि जिस इलाके के साथ सबसे ज्यादा अन्याय होता रहा है उसी इलाके के अपने साथी को हमने सिंचाई विभाग दिया है, यह जिम्मेदारी दी है ताकि वे अपना काम मेहनत से कर सकें। अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए सारा हरियाणा बराबर है लेकिन जिसका जो हक है वह उसको जरूर मिले। मैं समझता हूं कि जो भी हरियाणा का हित समझता है वह इस बात से जरूर सहमत होगा कि सभी जिलों को बराबर पानी मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जल संरक्षण के बारे में बहुत बातें यहां पर की गईं। आप जी०टी० रोड पर देखें। करनाल की भूमि या कुरुक्षेत्र की भूमि जो कि बहुत उपजाऊ है, सोना उगा रही है लेकिन जिस स्पीड से वाटर लैवल नीचे जा रहा है उसको देखते हुए आज से दस साल बाद वहां कुछ होने वाला नहीं है इसलिए आज से ही वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे और वह कदम हम उठाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यहां पर हमारे साथी ने

एस0वाई0एल0 की चर्चा की। एस0वाई0एल0 पर चर्चा कई बार यहां पर ओम प्रकाश चौटाला भी करते थे। हमने उस वक्त इस बारे में प्रस्ताव भी पास किए। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी चर्चा हुई कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है तो मैं कहना चाहूंगा कि जो एस0वाई0एल0 का इतिहास जानता है, हरियाणा का इतिहास जानता है उसको यह मालूम होना चाहिए कि एस0वाई0एल0 की शुरुआत कहां से हुई। एस0वाई0एल0 के निर्माण के लिए सबसे पहले उदघाटन कस्सी मारकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। उस समय वे केन्द्र में प्रधानमंत्री थी। इस बारे में जो फैसले हुए चाहे वह राजीव-लौंगोवाल समझौता हो वह भी राजीव जी के समय में ही हुआ। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय में भी यह मुद्दा उठाया गया और यह भी सही है कि हरियाणा में इस मुद्दे पर कई सरकारें बनी हैं और कई सरकारें गिरी भी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें यह सोचना पड़ेगा कि हरियाणा में अब तक अगर एस0वाई0एल0 नहीं बनी है और इसमें इतना विलम्ब हुआ है तो इसके लिए दोषी कौन है? अध्यक्ष महोदय, यह बात अब सिद्ध हो गई है, कैसे सिद्ध हो गई है वह मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हित में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसका आधार क्या माना है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका आधार माना है राजीव लौंगोवाल समझौता और राजीव लौंगोवाल समझौते का विरोध किसने किया है? अध्यक्ष महोदय, इतिहास साक्षी है, हरियाणा के लोग साक्षी हैं कि उसका विरोध उस समय लोकदल

ने किया। पता नहीं उनकी पार्टी का उस समय क्या नाम था लेकिन चौधरी देवीलाल जी उसके अध्यक्ष थे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी इस समझौते का विरोध किया है। जो आज चर्चा कर रहे हैं यह तो सबके सामने है। न्याय युद्ध का नाम लेकर यहां पर उसका विरोध किया गया।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में कुछ कहना है।

Shri Bhupinder Singh Hooda : I am not yielding. इन्दौरा साहब, आप तो पार्लियामेंट में रहे हैं कोई नये सदस्य नहीं है।

Mr. Speaker : Take your seat Mr. Indora Ji. That is not the way.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह विरोध किसने किया? इसमें जो इतना विलम्ब हुआ है वह किसकी वजह से हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस समय वहां पर चौटाला साहब की सरकार की और केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हरियाणा के हक में लेकिन उसके बाद में 1.5 साल तक वह फैसला ठंडे बस्ते में रहा। उस समय न तो चौटाला साहब की सरकार ने कुछ किया जबकि असैम्बली ने इसके लिए उनको अधिकृत किया था। मैंने खुद उधार खड़े होकर कहा था कि आप इस बारे में कदम उठाओ

जहां पर भी आप कहेंगे हम चलेंगे पूरा सहयोग देंगे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर साथ देंगे लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। 1.5 साल तक वह फैसला लटका रहा। अध्यक्ष महोदय, आज ये कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बनी उसी दिन हम उनसे मिले। अध्यक्ष महोदय, उस दिन भी मैं सांसद था और जब तक मैं इस्तीफा नहीं देता तब तक मैं सांसद हूँ बाकी आपकी दया से मैं यहां पर हूँ। मेरे अलावा और भी कांग्रेस के 9 सांसद थे। जिस दिन सरकार बनी उसके थोड़े ही दिन बाद हम वहां केंद्र सरकार में मिले और जो डेढ़ साल तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठंडे बस्ते में रखा था, उसका उस समय केन्द्र सरकार ने फैसला किया कि जो एस0वाई0एल0 का बकाया निर्माण किया है वह सी0पी0डब्ल्यू0डी0 करेगी, पंजाब सरकार नहीं करेगी। यह काम केन्द्र में जब बी0जे0पी0 की सरकार थी उन्होंने भी नहीं किया। पंजाब की असैम्बली में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं वहां एक गैर कानूनी एक्ट पंजाब की सरकार ने पास किया और जो जल समझौता था, उसको निरस्त करने का काम किया। फिर हम सारे सांसद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिले और श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिले। सुबह हम मिले और उसी भाम को कैबिनेट की मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि रैफरेंस के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास केस भेज जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो केस पड़ा है वह क्या है? सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने जो गैर कानूनी और गैर इखलाकी एक्ट पास किया है

उसका रैफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने नहर के निर्माण के बारे में जो फैसला हमारे हक में कर ही रखा है। अभी दो दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि पंजाब के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि जो जल विवाद है उसके लिए हम बातचीत करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि बातचीत की गुंजाइश ही कहां है? जो गलत कानून पंजाब ने पास किया है उसको निरस्त करो, उसी निरस्त किए बगैर हरियाणा कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। यह हमारे लिए जीवन रेखा का प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि विपक्ष के साथियों से भी मैं पूरा सहयोग मिलेगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बारे में तथ्य की बात बताई है। सबको मालूम है कि यह नहर हरियाणा की जीवन रेखा है विलंब क्यों हुआ है मैं इसके पिछली इतिहास में जाना नहीं चाहता। हम सब मिलकर हरियाणा के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। ओम प्रकाश चौटाला ने तो इराड़ी कमिशन को भी काले झण्डे दिखाये थे जिन्होंने हमारे हक में समझौता किया था। (Interruptions) I am not yielding. I have gone through the facts.

Dr. Sushil Indora : If you are not yielding. Why should I intervene?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में है। रैफरेंस का भी जल्दी फैसला होगा और हम अपना हक लेकर रहेंगे। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हम पंजाब को कह रहे हैं कि वह हमारे हक का पानी नहीं

दे रहा है तो हमें भी उस कसौटी पर खरा उतरना चाहिए कि हरियाणा द्वारा जिन राज्यों को पानी का हिस्सा दिया जाना बनता है वह हरियाणा को भी देना चाहिए। हम पंजाब को अपना बड़ा भाई कहते हैं और कहते हैं कि पानी का हमारा हक है और वह उसे हमें देना चाहिए। बिजली की बात हुई। बिजली का बहुत ही इम्पोर्टेंट सैक्टर है। बिजली के बगैर विकास की बात नहीं सोची जाती इसलिए किसानों के बिजली बिलों की बात हुई। एक-एक किसान पर इतना बोझ लगा दिया है कि वह अपनी सारी जमीन गिरवी रख दे और उसके बच्चे भी सारी उम्र कमाते रहें तो भी वह कर्जा नहीं उतार सकता। बिजली के लिए पॉवर सैक्टर का और स्वास्थ्य के लिए उसकी आमदनी का बढ़ना जरूरी है। आज सबको यदि बिजली देनी है तो उसके लिए यह जरूरी है कि ट्रांसमिशन लोसिज कम हों। हरियाणा में मेरे ख्याल में 40-44 प्रतिशत के करीब ट्रांसमिशन लोसिज हैं जबकि पंजाब में 17 या 18 परसेंट लाइन लोसिज हैं। आज हमें ट्रांसमिशन लोसिज और चोरी कम करने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। इन लोसिज को कम करने के बारे में सुरजेवाला जी ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। हमारी कोशिश होगी कि प्रदेश में कैप्टिव पॉवर स्टेชัน हों। पुराने बिजली के बिलों की सैटलमेंट हो सके उसके बिना हमने कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों की एक पांच मेंबरों की समिति बनाई है।

17:00 बजे

जो जल्दी ही अपना कार्य भुरू करेगी और इन चीजों का निपटारा करेगी। वित्त मंत्री जी उस कमेटी को हैड कर रहे हैं, एक्साईज एण्ड टैक्स एन मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, इरीगे एन मिनिस्टर यानी 5 वरिष्ठ मंत्री इस कमेटी के सदस्य हैं जो इस बात का निपटारा करेंगे ताकि हमारे यहां पूरी बिजली हो और सस्ती बिजली हो। अभी उदयभान जी ने फरीदाबाद की चर्चा की कि फरीदाबाद का एन0टी0पी0सी0 का प्लांट है उसकी क्षमता 432 मैगावाट है। उन्होंने कहा कि उस प्लांट से हरियाणा को पूरी बिजली नहीं मिल रही है। उसका कारण है, वहां जो प्लांट एन0टी0पी0सी0 ने लगाया था वह सी0एन0जी0 के नाम से लगाया था और जो सी0एन0जी0 से बिजली पैदा होती है उस प्लांट में वह हरियाणा को 1.90 या 2.20 रूपए के भाव से मिलती है। जितनी उस प्लांट की कैपेसिटी है उस हिसाब से हमें 75 प्रति ात बिजली मिल रही है। बकाया जो 25 प्रति ात बिजली है वह हम नाथपा से प्राप्त कर रहे हैं जिसका भाव 4.00 रूपए प्रति यूनिट है। सवाल यह है कि हम इतनी महंगी बिजली क्यों लें? क्योंकि गैस की सप्लाई पूरी नहीं है इसलिए हमें महंगी बिजली बाहर से लेनी पड़ रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि हरियाणा की बिजली की कमी पूरी हो गई है या हम अपने हिस्से की पूरी बिजली नहीं ले रहे हैं। इसके बहुत से कारण हैं और एक लम्बी बात है। यहां पर बिजली का पूरा उत्पादन हो, ट्रांसमि एन लौस कम हो, पूरी बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले और यह जब तक नहीं होगा तब तक हरियाणा पूरा विकास नहीं कर सकता। हम

इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस बारे में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। मैं अब तीसरा स्वास्थ्य की बात करता हूँ। सबको मालूम है कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। लेकिन खासतौर से गांव के गरीब आदमी को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। पिछली सरकार के समय में पर्ची की बात थी हम इसे एग्जामिन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बैठी हैं। पिछली सरकार की यह बात मुझे बहुत अखरती है कि पोस्टमार्टम के लिए 120 रूपए लिए जाते थे वह आज से ही खत्म किए जा रहे हैं। अब पोस्टमार्टम पर कोई पैसा नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति मर जाए और उसके परिजनों को ऊपर से फीस भी देनी पड़े। गरीब आदमी यह फीस कहां से देगा। हम को... करेंगे कि नीचे एक यानी देहात तक स्वास्थ्य सेवाएं जाएं। श्री नरे... यादव जो अटेली से जीत कर आए हैं। एक अजीब बात उन्होंने बताई कि वहां के अस्पताल की एक्स-रे की म... रिन रिपेयर के लिए गई थी और वह अब तक वापिस नहीं पहुंची। मैं नरे... जी को बताना चाहूंगा कि एक हफ्ते तक अस्पताल में एक्स-रे म... रिन पहुंच जाएगी। जो बात हमारे घोशणा पत्र में भी नहीं है मैं भी ऐसी बात नहीं कहूंगा, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जो बात संभव होगी वही जुबान से कही जाएगी। हम सब चीजों पर विचार करेंगे। महिलाओं का स... क्तिकरण होगा। पीने के पानी के लिए वि... श तौर से दक्षिणी हरियाणा में जहां पीने का पानी भी नहीं है स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। गांव में भाहरी सुख सुविधा देने का हमारा पूरा प्रयास होगा। क्योंकि गांव से भाहरों की तरफ

पलायन रोकने के लिए गांवों में भाहरी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जहां तक इण्डस्ट्रीज की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि वह गांवों में सामाजिक बुराई के रूप में तबदील होती जा रही है। खाली भूख से ही नहीं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए साधन उपलब्ध कराए जाएं। यह प्राथमिकता इस सरकार की रहेगी उसके लिए अन्तर और ज्यादा न बढ़े इसलिए यह आवयक है कि यहां राज्य में औद्योगिकीकरण हो। एक ऐसा माहौल प्रदे 1 में बनाना पड़ेगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। जो अच्छे उद्योग पिछले पांच साल में प्रदे 1 को छोड़ने की बात कर रहे थे, जैसे कानून और व्यवस्था की बात है, भ्रष्टाचार की बात है भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा और कानून व्यवस्था में सुधार होगा। भान्ति का प्रयास होगा तभी कोई बाहर से आकर उद्योग लगाएंगे क्योंकि ग्लोबलाईजे 1न और लिब्रलाईजे 1न का जमाना है उसका फायदा हरियाणा प्रदे 1 को बहुत मिल सकता है क्योंकि हम दिल्ली के तीन तरफ हैं और हम पूरी फ़ैसिलिटीज उनको देंगे We shall facilitate and not control the investments. जो लोग बाहर से हमारे यहां इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आएंगे उनको पूरी फ़ैसिलिटीज देंगे, हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, हम उन पर अपनी बात नहीं थोपेंगे कि आप यह कर दो वह कर दो। जब हम उन पर अपनी बात न थोपने का माहौल बनाएंगे तभी कोई उद्योगति अपना उद्योग लगाने के लिए हरियाणा में आएगा। सो 1ल वैल्फेयर के बारे में यहां चर्चा हुई। हमारी बहन जी ने

जवाब दिया कि ओल्ड ऐज पैँ उन देना हमारी जिम्मेवारी है और ओल्ड ऐज पैँ उन कांग्रेस पार्टी की नीति हैं इंदिरा गांधी जी ने इस नीति को सोचा था लेकिन पैँ उन के बारे में बहुत सी विचारयतें हैं कि जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही है और जिसको नहीं मिलनी चाहिए उसको मिल रही है इसकी पूरी छानबीन होगी और सही आदमियों को पैँ उन दी जाएगी। जब पैँ उन की जरूरत होती है तब नहीं मिलती सरकार इस बात का भी पूरा प्रबंध करेगी कि पैँ उन हर महीने की 7 तारीख को मिल जाए ताकि वह पैसा उसके काम आ सके। मैं और मेरे साथियों ने यह फैसला किया है। आज से 75 साल पहले महात्मा गांधी जी ने डांडी यात्रा साबरमती से लेकर डांडी तक की थी। हमने भी अभी 18 तारीख को डांडी यात्रा की जिसकी भुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी करके आई थी। 75 साल पहले यह घटना हिन्दुस्तान में हुई थी जिसमें एक नमक की चुटकी ने पूरे देश में एक लहर फैलाई और एक चेतना जगाई जिसका नतीजा हमें आजादी के रूप में मिला। सोनिया गांधी ने 75 साल के बाद पुनः डांडी यात्रा की भुरुआत की और मुझे भी अपने साथियों के साथ इस यात्रा में 18 तारीख को शामिल होने का मौका मिला। गांधी जी का सपना साकार हो, इस वास्ते मैंने और मेरे कहने पर मेरे साथियों ने यह फैसला किया है कि हम कोई भी फैसला करने से पहले गांधी जी जो कहकर गए थे उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। गांधी जी जी ने कहा कि कोई फैसला करने से पहले उस व्यक्ति की तस्वीर जो उस प्रदेश का सबसे गरीब आदमी हो और उसको

उस फ़ैसले से क्या लाभ हानि पहुंचने वाला है, का चेहरा देखकर फ़ैसला लें। हम हरियाणा में व्यवस्था ऐसी करेंगे कि सामाजिक सीढ़ी में जो अन्तिम पांव सीढ़ी पर खड़ा है उसको लाभ हो ताकि गरीब आदमी का जीवन स्तर ठीक हो सके। जो पैसे वाले हैं। जिसका अच्छा स्तर है वे यहां नहीं रहें वे तो दिल्ली चले जाएंगे या अन्य भाहरों में चले जाएंगे। हम चाहेंगे कि गांव और भाहर के गरीब आदमी का जीवन स्तर अच्छा हो। हमारी सरकार चाहती है कि लोगों की हर फ़ैसले में भागीदारी हो। सरकार बदल जाने के बाद भी कार्य होते रहने चाहिए, सिर्फ चेहरे बदलने से काम नहीं रूकने चाहिए। हम पुरानी व्यवस्था को बदलें और उस व्यवस्था से भ्रष्टाचार और भय को निकालकर उखाड़ फेंकेंगे। यह बात केवल राजनेताओं पर ही लागू नहीं होगी बल्कि निचले लैवल तक लागू होगी। मैं आज सभी को चेतावनी दे रहा हूं और आज मुझे चेतावनी देने का मौका मिला है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो भी हो चाहे वह तहसील हों, चाहे वह थाना हो या कोई और जगह है जो प्रथाएं, व्यवस्था उनमें काम करने की बनी हुई हैं, वे अपना काम ठीक प्रकार से करें और वे मुख्य धारा में आ जाएं। अगर कोई पकड़ा गया तो उसे नहीं बका जाएगा। पिछली सरकार के समय कोई गरीब आदमी अपनी बेटी की भादी करने के लिए जमीन बेचता था तो उसके लिए उसको कहा जाता था कि इतने परसेंट दे दो। अब हमें सारी व्यवस्थाएं बदलनी हैं। अध्यक्ष महोदय चौधरी भाम डेर सिंह जी ने कहा और मैं भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बदले की भावना से कोई

कार्यवाही नहीं करती लेकिन यह भी हकीकत है कि गलत कार्यों की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, छोटे से लेकर बड़े तक किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे साथी कर्ण सिंह दलाल जी कह रहे थे कि हमारी सरकार किस तरह से दोशियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी और इस बारे में सरकार की क्या नीति है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह बात आज यहां स्पष्ट करने वाली नहीं है अगर आज यह बात स्पष्ट कर दी तो जो दोषी हैं वे अपना बचाव ढूंढ लेंगे। समय पर सही तरीके से कार्यवाही होगी और हमारा प्रयास होगा कि कोई भी दोषी बच न सक। चक्की चलती है तो पीसती भी है लेकिन बारीक पीसने में थोड़ा समय लगता है। इसमें हम सभी का सहयोग लेंगे। हम बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। बदले की भावना से कार्यवाही करना कांग्रेस पार्टी की नीति भी नहीं है। पिछले 6 सालों का भासन का एक युग था। हमारे लिए और प्रदे 1 की जनता के लिए युग का मतलब एक बुरा सपना था, भयानक सपना था। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस बुरे और भयानक सपने को भुलाना है और जो लोग दोषी हैं उनको दण्डित करना है। मेरी साथियों से प्रार्थना है कि सभी साथी रचनात्मक सुझावों के बारे में सोचें और उस भयानक सपने को भूल जाएं और प्रदे 1 के हितार्थ कार्य करें। हमें इधर-उधर की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर प्रदे 1 की भलाई के बारे में सोचना है और हमारी संस्थाओं की प्रतिष्ठा को कायम करने का कार्य करना है। आज मैं असैम्बली में हूँ, पांच साल पहले भी रहा

और पार्लियामेंट में भी रहा। इंदौरा साहब भी मेरे साथ पार्लियामेंट में रहे हैं और आज की इस असैम्बली में ऐसे 10 माननीय सदस्य हैं जो पार्लियामेंट में भी रहे हैं। हमारा सबका यह प्रयास रहेगा कि इस संस्था की, लैजिसलेचर की प्रतिष्ठा बनी रहे और इस प्रतिष्ठा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारे अध्यक्ष जी बड़े काबिल और अनुभवी भाखिसयत वाले हैं। इनकी देखरेख में सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सभी साथियों को अपने विचार रखने की खुली छूट होगी और सभी साथी रचनात्मक सुझाव दे सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की राजनीति में आज कांग्रेस पार्टी का भासन है और मैं उसका हैड हूँ, मुख्यमंत्री हूँ। पहले ऐसा होता रहा है कि जो भी सदस्य अपना सुझाव देना चाहता था उसके सुझाव सुने नहीं जाते थे और चौटाला साहब की आंख और उंगली के इतारे से ही सदस्यों को बोलने दिया जाता था। यदि कोई सदस्य जनता की बात यहां पर कहता था तो उसकी बात सुनी नहीं जाती थी। अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने न तो स्वयं कोई जनहित के कार्य किए और न ही दूसरों की बातें सुनते थे। यदि वे जनहित के कार्य करते तो आज उनकी यह हालत न होती। यदि लोक सभा के चुनावों के बाद भी वे कुछ सीख लेते तो उनकी हालत इतनी बुरी नहीं होती कि वे विपक्ष के नेता भी न बन सकें। सरकार तो उनकी आनी नहीं थी। स तरह की उनकी तानाशाही थी कि उनकी सरकार के समयमें कोई भी सदस्य अपने विचार खुलकर नहीं रख सकता था। लेकिन उन्होंने अपने सदस्यों को यह छूट दे रखी थी कि वे हमें

कुछ भी कहें, हमारे ऊपर व्यक्तिगत अटैक करें और हमारी तरफ से जब कोई सदस्य बोलता था तो उसे बोलने नहीं दिया जाता था। अध्यक्षमहोदय, वे ऐसा क्यों करते थे यह तो वे ही जाने लेकिन जो भी सदस्य चुनकर आया है उसे बोलने का अधिकार है। अपनी बात कहने और रचनात्मक सुझाव देना उसका अधिकार है। जहां तक मैं समझता हूं, वे यह सोचते थे कि यदि उनकी पार्टी का कोई सदस्य उनकी इच्छा के बगैर बोलेगा तो वह डिसीडेंट हो गया। इस तरह की उनकी तानाशाही प्रवृत्ति थी। लेकिन अब हमें यह सब कुछ बदलना होगा इसी से हमारे प्रदेश का विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को विवास दिलाता हूं कि सभी सदस्य सरकार की नीतियों पर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकेंगे और रचनात्मक सुझाव दे सकेंगे। विपक्ष न के बराबर है। सभी अच्छे साथी चुनकर आये हैं। सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं इनके बिना प्रजातंत्र कायम नहीं हो सकता। मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि विपक्ष का काम भी सत्तापक्ष को करना है। हमारा कोई भी साथी खुलकर रचनात्मक सुझाव दे सकता है और सरकार की आलोचना कर सकता है। जो भी साथी सही आलोचना करेगा मैं उसको निजी आलोचना नहीं मानूंगा बल्कि इस बात को मैं एक सुधारक के रूप में ग्रहण करूंगा। हमारे साथी जो भी रचनात्मक सुझाव देंगे सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करेगी। जिससे प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। प्रदेश को पूरा लाभ तभी होगा जब हम पूरी व्यवस्था को बदलें और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ायें सही

मायने में हाउस में भी प्रजातंत्र कायम हो। आप सभी अपने अपने इलाके से चुन करके आए हैं और लोगों को आपसे बहुत सी आ गए और उम्मीदें भी हैं। लोगों ने आपको मान सम्मान के साथ चुन करके भेजा है। आपको यहां पर पूरा मान सम्मान मिलेगा। अगर आप ठीक कार्य करेंगे, रचनात्मक सुझाव देंगे सरकार उनको गंभीरता से लेगी तथा उन सुझावों पर अमल होगा। सभी साथियों की तरफ से बहुत सी बातें आई हैं उनको अब मैं गिना नहीं सकता। मैं सभी साथियों की बातें गहराई से सुन रहा था। जिन साथियों ने रचनात्मक सुझाव दिए हैं। हम उन सब सुझावों पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं भावों के साथ मेरा आपके माध्यम से सभी साथियों से निवेदन है कि जो प्रस्ताव चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया है उसको सर्वसम्मति से पास करें। इन भावों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is-

“That an Address be presented to the Governor in the following terms :-

“That the Members of the Haryana Vidhan Sabha Assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 22nd March 2005.”

The motion was carried.

वर्ष 2004-2005 के लिए अनुपूरक अनुमान

(दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 2004-2005.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 2004-2005.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Shri Shadi Lal Batra, Chairperson Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2004-2005.

Shri Shadi Lal Batra (Chairperson, Committee on Estimatee) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2004-2005.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 23rd March, 2005.

17.19 hrs.

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. Wednesday, the 23rd March, 2005)